जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:29 अंक:217 दिनांक:18-07-2024 गुरूवार मूल्य:1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

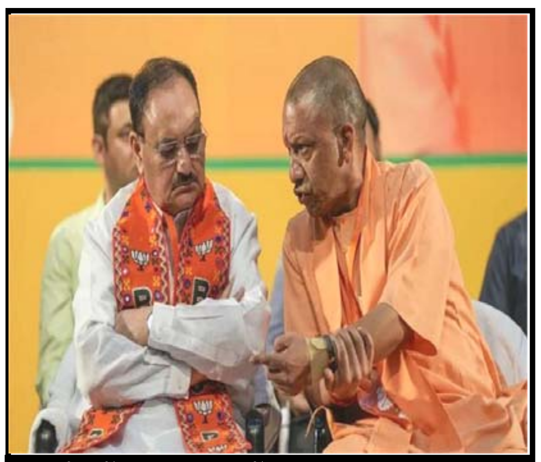

उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन में फिलहाल कुछ आंशिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। संगठन के कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत चर्चा का विषय बनी हुई है।

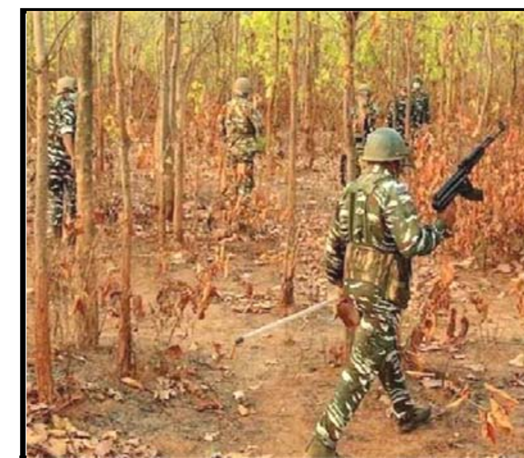

छत्तीसगढ़ के गढ़चिरोली में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरु हो गई है। इस एनकाउंटर में सेना के जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया है।

यूपीः चुनाव को लेकर महामंथन

(नई दिल्ली) भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बाद अमित शाह पीएम मोदी से मिलने पहुंचे

नई दिल्ली (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकत की है। इसके कुछ ही देर बाद गृहमंत्री अमित शाह पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी चुनाव को लेकर यह महामंथन हो रहा है। यह भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। शाम साढ़े पांच बजे बीजेपी मुख्यालय पीएम मोदी पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यालय के कर्मचारियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से जुड़े तथ्यों से अवगत कराया है। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले उत्तरप्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर उन्हें प्रदेश के राजनीतिक हालात, संगठन की हालत और लोकसभा चुनाव में आए नतीजे से जुड़े तथ्यों से अवगत कराया था।

उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली में मेल-मुलाकातों और बैठकों का यह दौर अभी आगे भी जारी रह सकता है।

इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश में भी हलचल नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात करने राजभवन पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है।

नासिक से टमाटर की आवक बढ़ने से कम हो जाएंगे दाम

नई दिल्ली(ईएमएस)। बाजार में अगस्त में नासिक से टमाटर की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है, जिससे टमाटर की कीमतों में कमी आ सकती है। हिमाचल से आने वाले माल में बारिश के कारण दाम बढ़े हैं, लेकिन आने वाले दिनों में दामों में गिरावट की उम्मीद है। व्यापारी अंकित सेतिया के अनुसार, रिटेल मार्केट में ग्राहकों की मांग दोगुनी है, जिसके कारण टोमैटो प्यूरी की बिक्री में तीन गुना तक वृद्धि हुई है। सप्ताह भर में आमतौर पर पांच से सात किलो की बिक्री होती थी, लेकिन इस बार इस आंकड़े ने बीस किलो तक का आंकड़ा छू लिया है। व्यापारी डिंपी सचदेवा बताते हैं कि अगस्त के अंतिम दिनों में नासिक से टमाटर की आपूर्ति आएगी, जिससे बाजार में दामों में कमी आ सकती है। इसके बाद लोकल टमाटर भी बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे दाम निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। मकसूदां सब्जी मंडी के थोक कारोबारी बताते हैं कि इन दिनों टमाटर की लोकल फसल खत्म हो जाती है तथा हिमाचल से ही टमाटर की आपूर्ति होती है। इस बार हिमाचल में लगातार बारिश के कारण माल की सप्लाई बाधित हो रही रही है। साथ ही दामों में भी रोजाना इजाफा हो रहा है। मकसूदां सब्जी मंडी में मंगलवार को बेंगलुरु से भी टमाटर की सप्लाई हुई है, लेकिन इसके दाम में थोक में 80 रुपये प्रति किलो हैं। ऐसे में बेंगलुरु से सप्लाई के बाद भी दामों में कमी की उम्मीद नहीं है। अगस्त में टमाटर की कीमतों में गिरावट आ सकती है।

लगातार बारिश से नदियां उफान पर...यूपी में 6, बिहार में 5 और कर्नाटक में 4 की मौत

मप्र, यूपी, बिहार में जानलेवा बारिश

नई दिल्ली(ईएमएस)। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। यहां तीन नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती और क्यूनो नदी के उफान पर होने के कारण गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर और गोंडा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर गंगा में डूब गया है। यह दुनिया का पहला झुका हुआ मंदिर है। पिछले 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 6 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि सभी की मौत डूबने से हुई है। वहीं बिहार में 5 के मरने की खबर है। इसके अलावा कर्नाटक में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं हरदा में बाइक समेत एक युवक बह गया।

बिहार में भी बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, मधेपुरा, अररिया समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 24 से ज्यादा निचले इलाकों के गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

- भोपाल-हरदा में तेज बारिश

भोपाल में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। इससे पहले दिन में उमस रही। बुधवार को मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम, आगर-मालवा, मंदसौर, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले में भारी बारिश का अलर्ट है।

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में नीमच, मुरैना, ग्वालियर, छतरपुर के खजुराहो और पन्ना में आकाशीय बिजली गिरने या चमकने और मध्यम गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इससे पहले हरदा में सुबह 4 घंटे बारिश हुई। आदमपुर और भैरोपुर में सडक़ों पर दो फीट तक पानी भर गया। एक युवक बाइक समेत नाले में बह गया। खंडवा में सुबह 9 बजे से रुक-रुककर बारिश हो रही है। बैतूल के मुलताई में करीब 11 बजे आधा घंटे तक पानी गिरा। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में सुबह 6 बजे से करीब 9:30 बजे तक बारिश हुई। मानसून ट्रफ मध्यप्रदेश से गुजर रही है। वहीं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया भी एक्टिव है। इस कारण पूरे प्रदेश में आंधी-बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। बारिश से नर्मदा समेत अन्य नदियां भी उफान पर आ रही हैं। प्रदेश में 21 जून से मानसून ने आमद दी थी, तभी से रुक-रुककर, कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हो रही है। आईएमडी भोपाल के वैज्ञानिक अशोक दामले ने बताया- सिस्टम की वजह से अगले पांच दिन तक तेज बारिश का दौर बना रहेगा।

यूपी में यह क्या हुआ, दोनों उपमुख्यमंत्री टीम से हुए बाहर

प्रदेश सरकार और संगठन में फेरबदल के कयास लगने लगे

लखनऊ,(ईएमएस)। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेजी से जोड़-तोड़ के साथ ही उठा-पटक शुरु कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई है, जिसमें प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री गायब हैं। सीएम योगी की टीम में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को शामिल नहीं किए जाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।

सीएम योगी की स्पेशल 30 टीम को यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने अपने स्पेशल 30 के जरिए ही यूपी में होने जा रहे उपचुनाव को जीतने का प्लान बना रखा है, इसमें दोनों ही उपमुख्यमंत्री नहीं रखे गए हैं। इस टीम में शामिल मंत्रियों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं-

सीसामऊ विधानसभा - सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल।

खैर विधानसभा - लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह।

करहल विधानसभा - जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल सिंह।

मिल्कीपुर विधानसभा – सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा।

कटेहरी विधानसभा - स्वतंत्र देव सिंह, आशीष पटेल और दयाशंकर मिश्र।

फूलपुर विधानसभा - दयाशंकर सिंह और राकेश सचान।

मझवां विधानसभा - अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद।

ग़ाज़ियाबाद सदर विधानसभा - सुनील शर्मा, बृजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल

मीरापुर विधानसभा - अनिल कुमार, सोमेन्द्र तोमर और केपीएस मलिक।

कुंदरकी विधानसभा - धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी।

इस सूची को देखने के बाद कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने सब ठीक नहीं चल रहा है।

गढ़चिरौली में पुलिस ने भीषण एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को मार गिराया

गढ़चिरौली (ईएमएस)। महाराष्ट्र के नक्सली प्रभावित गढ़चिरौली में पुलिस ने भीषण एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों और पुलिसवालों के बीच तकरीबन 6 घंटे तक मुठभेड़ चली। भीषण एनकाउंटर में पुलिस ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया। कुछ नक्सलियों के मौके से भागने की भी सूचना है।

गढ़चिरौली में पुलिस-नक्सली एनकाउंटर में 2 जवानों को भी गोली लगने की बात सामने आई है। घायल दोनों जवानों को बेहतर इलाज के लिए नागपुर शिफ्ट किया गया। जानकारी के अनुसार, दोनों अब खतरे से बाहर हैं। हाल फिलहाल के दिनों में गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली यह बड़ी सफलता है। जवानों ने मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बराम किया है। सात ऑटोमैटिक राइफल के साथ ही 3ंख-47 भी जब्त की गई है। बता दें कि यह मुठभेड़ कांकेर और गढ़चिरौली की सीमा पर हुई है।

गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनकाउंटर टीम में शामिल जवानों के लिए बड़ी घोषणा की है। फडणवीस ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराने वाले पुलिसकर्मियों को 51 लाख रुपये बतौर इनाम देने का ऐलान किया है। बता दें कि पुलिस और नक्सलियों के बीच तकरीबन 6 घंटे तक मुठभेड़ चली। जानकारी के अनुसार, मुठभेड़ बुधवार दोपहर बाद शुरू हो गई थी, जो देर शाम तक चलती रही। इसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दोपहर में भारी गोलीबारी शुरू हुई और देर शाम तक रुक-रुक कर 6 घंटे से ज़्यादा समय तक जारी रही। इलाके की तलाशी में अब तक 12 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। अब तक तीन एके 47, दो इंसास, एक कार्बाइन, एक एसएलआर समेत सात स्वचालित हथियार बरामद किए गए हैं। मरने वाले माओवादियों में टिपागड़ दलम के इंचार्ज डीवीसीएम लक्ष्मण अत्राम उर्फ विशाल अत्राम की पहचान की गई है। माओवादियों की पहचान और इलाके की तलाशी जारी है। मुठभेड़ में सी60 के एक पीएसआई और एक जवान को गोली लगी है। वे खतरे से बाहर हैं। उन्हें निकाल लिया गया है और इलाज के लिए नागपुर भेज दिया गया है।

चार राज्य में फैला चांदीपुरा वायरस....100 में से 70 बच्चों की हो जाती हैं मौत

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश के चार राज्यों में खतरनाक देसी वायरस चांदीपुर ने अपने पांव पसार लिए हैं। जिससे मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी पुणे को अलर्ट पर रखा गया है। एम्स में पीडियाट्रिक विभाग के पूर्व एचओडी डॉ. एम बाजपेयी ने बताया कि इस वायरस के चपेट में आने से 100 में से 70 बच्चों की मौत हो सकती है। डॉ बाजपेयी ने कहा कि इसमें मोर्टेलिटी 56 से 70 फीसदी तक है। डॉ. बाजपेयी ने बताया कि वायरस में बहुत कम समय में यानी की 24 से 48 घंटे में मृत्यु हो सकती है। इसलिए जरूरी यह है कि हाइजीन का ध्यान रखें। फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहने। मच्छरों से बच्चे। जैसे ही लक्षण होता है अस्पताल तुरंत जाएं। इसमें कोई एंटी वायरस थैरेपी नहीं होती है।

डॉ.बाजपेयी ने कहा कि जैसे फ्लू के साधारण लक्षण होते हैं इसमें भी लगभग वहीं लक्षण दिखाते हैं, जैसे कि बुखार आता है, सिरदर्द होता है, डायरिया हो सकता है, दौरे भी पड़ सकते हैं, यह ब्रेन को बहुत ही जल्दी पकड़ता है। बहुत जल्दी बच्चा कोमा में चला जाता है और मौत तक हो सकती है। इसलिए इस मौसम में इस तरह के लक्षण आने पर उसे हल्के में ना लें।

गुजरात में अपने पांव पसारने के बाद चांदीपुरा वायरस ने महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। सभी बच्चों के खून के सैंपल पुणे की राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजे गए हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि जहां चांदीपुर वायरस के फैलाव सामने आया है वहां अब तक 8600 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। यहां पूरे इलाके को 26 जोन में बांटा गया गुजरात में अब तक चांदीपुरा वायरस संक्रमण के 14 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं।

जन हितैषी

गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में उतरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कहना है, कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शरिया कानून के खिलाफ है। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा है, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वह सभी कानूनी उपायों पर विचार कर रहा है। गौरतलब है, कि 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कि गुजारा भत्ता, दान अथवा धर्म से जुड़ा मामला नहीं है। गुजारा भत्ता पाना विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है, कि हमारे संविधान ने हर धर्म की महिला को समान हक देने का कानून बनाया है। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है, जितना अन्य धर्म की महिलाओं और बच्चों को है। शादी या निकाह होने के बाद जब पति-पत्नी के बीच में तलाक होता है। ऐसी स्थिति में तलाकशुदा पत्नी और उसके बच्चों के भरण-पोषण करने की जिम्मेदारी पिता और पति की ही होती है। भारत में अधिकांश महिलाएं घरेलू कामकाज करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करती हैं। उनका स्वयं का कोई आर्थिक आधार नहीं होता है। जब शादी और निकाह के बाद पति-पत्नी के संबंध बनते हैं, उनसे बच्चे पैदा होते हैं। ऐसी स्थिति में पत्नी और बच्चों के जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी आर्थिक रूप से पति की होती है। ज़ब पत्नी की कोई कमाई नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा गुजारा भत्ता के रूप में आमतौर पर पति के वेतन या कमाई का 20 से 25 फ़ीसदी हिस्सा भरण पोषण के रूप में देने के आदेश दिए जाते हैं। तलाक के पहले जिन परिस्थितियों में पत्नी और बच्चे रह रहे थे। उसके मुताबिक उनके आगे का भी जीवन-यापन और शिक्षा इत्यादि के लिए आर्थिक आधार मिले। इसके लिए गुजारा भत्ते का नियम, सभी जाति और सभी धर्म की महिलाओं के ऊपर समान रूप से लागू होता है। पति की आर्थिक स्थिति के आधार पर न्यायालय द्वारा गुजारा भत्ता तय किया जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की आड़ में मुस्लिम महिलाओं का शोषण वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम महिलाओं को निकाह के समय मेहर के रूप में एक राशि तय कर दी जाती है। जब तलाक होता है, मेहर की रकम को ही तलाक का मुआवजा मान लिया जाता है। मेहर की रकम देकर पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण और शिक्षा इत्यादि की जिम्मेदारी से मुस्लिम पति अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लेते हैं। जिसके कारण मुस्लिम समुदाय में तलाकशुदा महिलाओं और उनके बच्चों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बहुत खराब है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है। वह तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते के लिए दिया गया फैसला है। संविधान ने धार्मिक आधार पर मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय को जो विशेष अधिकार दिए हैं। वह धार्मिक क्रियाकलापों के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला परिवार की जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ फैसला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इस फैसले का विरोध करना कहीं से भी जायज नहीं माना जा सकता है। नाहीं इसे मुस्लिम धर्म और धार्मिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का 10 जुलाई को दिया गया फैसला सीआरपीसी की धारा 120 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण से जुड़ा संवैधानिक अधिकार है। मुस्लिम महिलाएं न्यायालय जाकर गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। यह अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी पहले से ही मिला हुआ था। एक पत्नी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उसे स्पष्ट किया है। मुस्लिम महिला का व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद है। इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। धर्म की आड़ लेकर महिलाओं का शोषण किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसे समझने की जरूरत है। इस मामले में कोई टकराव मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करती है तो उससे मुस्लिम समाज को ही नुकसान होगा। यह मामला धर्म से नहीं बल्कि परिवार और अर्थ से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे संवेदनशील विषय पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

बजट का हलुवा और हलुए का बजट

भारत अनोखा देश है। यहां सब कुछ अनोखा होता है ,जो दुनिया के शायद तमाम देशों में न होता हो। भारत में सरकार बजट पेश करने से पहले एक समारोह करती है जिसे अंग्रेजी में हलुवा सेरेमनी कहते हैं। इस हलुवा समारोह का लिखित इतिहास मुहे तो खोजने पर नहीं मिला,लेकिन जाहिर है कि इसके पीछे भी कांग्रेस ही रही होगी ,क्योंकि आज का भारत तो 2014 के बाद का भारत है। आज के भारत में स्टेशनों,शहरों और कानूनों के नाम बदले गए लेकिन गनीमत है कि इस हलुवा सेरेमनी को अभी तक हाथ नहीं लगाया गया है।

भारत में हलुवा और बजट आम आदमी के लिए ही बनाया जाता है। हलुवा सबसे सस्ता और सुलभ मिष्ठान भी है। गांवों से लेकर शहरों तक लोकप्रिय है। अमीर-गरीब सभी इस हलुए को पसंद करते हैं। शायद अंग्रेज भी करते हों। हलुवे की लोकप्रियता कालांतर में इतनी बढ़ी कि इसे मुहावरे का सम्मान मिल गया। किसी भी काम में व्यापक पैमाने पर भ्र्ष्टाचार या गोलमाल करने को भी हलुवा करना ही कहा जाता है। हलुवा बनाना और हलुवा करना एक ख़ास कला है ,इस्सके कलाकार ज्यादातर सियासत में या नौकरशाही में मिलते हैं। जहाँ ईमानदारी से हलुवा बनता है वो जगह केवल गुरुद्वारा है ,लेकिन गुरुद्वारों में बनने वाले हलुवे को हलुवा नहीं कड़ा-प्रसाद कहा जाता है। हलुवा जब प्रसाद बन जाता है तो आत्मा को सुकून देता है ,लेकिन जब हलुवा बजट बनता है तो हमेशा मीठा नहीं लगता।

वैसे आपको बता दूँ कि हलुआ एक प्रकार का मिष्टान्न है जिसकी उत्पत्ति फ़ारस से हुई है और व्यापक रूप से पूरे मध्य पूर्व में फैली हुई है।। हलुवा साधारणतः आटे, सूजी, गहि और शर्करा से बनता है। बाद में आप इसमें बारीक पिसे हुए बीज या बादाम भी मिला सकते हैं आजकल तो हर चीज का हलुवा बननी लगा है जो बजट हलुवे से सर्वथा भिन्न होता है। हलुवा अब हैसियत से बाबस्ता हो गया है। जिसकी जैसी हैसियत उसका वैसा हलुवा। मठ का अलग,मंदिर का अलग और कर्तव्यपथ का लग किस्म का हलुवा होता है। मुंबई वालों का हलुवा तो सबसे अलग होता ही है। माँई अनंत की शादी में किस तरह का हलुवा बना हमें पता नहीं।

इस साल के बजट का हलुवा समारोह नार्थ ब्लाक में सम्पन्न हो गया । आम बजट के हलुवे को किसने बनाया मुझे नहीं पता, किन्तु केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले ये बजट हलुवा अपने मंत्रालय के अधिकारीयों और कर्मचारियों में तकसीम किया। इसी नार्थ ब्लाक में बजट छपने वाली छपाई मशीन लगी है । ताकि बजट लीक न हो। बजट लीक हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । फर्क इस बात से पड़ता है कि बजट में हलुवे की जो मिठास है वो आम आदमी तक भी पहुँच पायेगी या नहीं ? देश में कांग्रेस ने दशकों तक बजट का हलुवा किया। अब एक दशक से भाजपा ये काम कर रही है। इस साल के बजट में तो भाजपा के साथ टीडीपी और जेडीयू को भी हलुवा करने का सौभाग्य मिला है।

कोई भी सरकार हो बजट में हलुवा करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की बजट में हलुवा करती ही है। ये बात और है कि अनेक राज्यों में हलुवा सेरेमनी नहीं होती। निर्मला जी मुझसे चार महीने छोटी हैं लेकिन मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। निर्मला जी के पास हलुवा बनाने की कोई उपाधि नहीं है किन्तु उन्होंने भाजपा सरकार के लिए सबसे ज्यादा बार बजट हलुवा तैयार किया। वे राजनीति में पिछले दरवाजे से ड राज्य सभा .आयीं थीं लेकिन वे पिछले छह -सात मर्तबा बजट हलुवा बनाने का सौभाग्य हासिल कर चुकी हैं। वे भाजपा की सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वित्त मंत्री हैं। उनके हलुवा बनाने पर किसी को संदेह नहीं हैसिवाय उनके अपने पति को ।भाजपा सरकार ने बीच में उन्हें हलुवा बनाने की जिम्मेदारी से मुक्त कर देश कोई रक्षा का और बाद में कारपोरेट का काम भी सौंपा लेकिन जब दूसरे वित्त मंत्री ढंग से बजट हलुवा नहीं बना पाए तो उन्हें वापस वित्त मंत्री बनाकर बजट हलुवा बनाने की जिम्मेदारी दे दी गयी।

देश में किसी भी दल की सरकार हो लेकिन आम जनता को उसके बजट हलुवे से तमाम उम्मीदें बनी रहतीं है। इस बार के बजट से देश के सभी वर्गों के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। आगामी बजट को लेकर आम लोगों को उम्मीद है कि इस बार उन्हें सरकार की तरफ से थोड़ी राहत दी जाएगी। चूंकि यह बजट आम चुनावों के बाद का पहला बजट है ऐसे में सरकार के लिए भी यह बजट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।

आम चुनाव में सरकार ले-देकर बनी है। इसलिए सरकार पर बजट को मीठा बनाने का दबाब है। सरकार के सामने कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी है। इस कारण सरकार द्वारा अपने वोट बैंक को भुनाने के लिए आम बजट में लोगों को खुश को लेकर ऐलान किए जाने की उम्मीद की जा रही है.

नौकरीपेशा यानी सैलरी क्लास से लेकर, महिलाएं, किसान, टैक्सपेयर्स और युवावर्ग तक के लोग इस बार के बजट में सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे है। उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट 2024 -25 पेश करेंगी तो उनके लिए कोई खास ऐलान किया जा सकता है। बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा । तब तक सभी को बजट हलुवे की महक से ही काम चलना पडेगा। बजट हलुवे का स्वाद कैसा होगा ये 23 जुलाई को ही पता चलेगा । भाजपा सरकार का नया बजट स्वाद में चाहे जैसा हो किन्तु उसका रंग तो भगवा ही रहने वाला है। देश का भगवाकरण हो रहा है तो बजट और उसका हलुवा इस रंग से कैसे बच सकता है।

इस समय देश को ऐसे हलुवे की जरूरत है जो किसानोन्मुखी हो। किसान हलुवा पेश होने की फ़िक्र किये बिना अपनी पुरानी मांगों को लेकर छह महीने का राशन -पानी लेकर दिल्ली आने वाले है। इस बार सरकार उन्हें दिल्ली आने से रोक भी नहीं सकती ,क्योंकि माननीय अदालत ने किसानों के दिल्ली जाने के अधिकार को संवैधानिक बता दिया है। अब देखना ये है की आने वाले दिनों में केंद्र द्वारा बनाया गया हलुवा फ़ैल तो नहीं जाएगा ? भगवान करे कि ऐसा न हो।(लेखक - राकेश अचल / ईएमएस)

दुनिया के सबसे बड़े खेल प्रतियोगिताओं में एक क्यों है ओलंपिक

23 जून 1894 को सोरबोन (पेरिस) में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन, प्रोमशन और रेगुलेट के लिए की गई थी। इसका विचार आईओसी सदस्य डॉक्टर ग्रस ने स्वीडन के स्टॉकहोम में रखा था। यह विचार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 41वें सीजन में रखा गया था। कुछ महीने बाद जनवरी 1948 में स्विट्जरलैंड के सेंट मोरित्ज में 42वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। परिणामस्वरूप पहली बार 23 जून 1948 को इंटरनेशनल ओलपंकि डे मनाया गया। ओलंपिक गेम्स' को खेलों का महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर चार साल में एक बार किया जाता है। इसे दुनिया के सबसे बड़े खेल प्रतियोगिताओं में से एक की मान्यता प्राप्त है। इसमें 200 से अधिक देशों के हज़ारों एथलीट कई प्रकार के खेलों में भागीदारी करते हैं।ओलंपिक दिवस 23 जून 1894 को बैरन पियरे डी कौबर्टिन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना को रेखांकित करता है ।अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के खेलों और खेलों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। चाहे वे किसी भी उम्र, लिंग, जाति या धर्म के हों। यह लोगों को शारीरिक व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस मौके पर कई खेलों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा, ओलंपिक खेलों के बारे में प्रदर्शनियां और एजुकेशनल सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है आधुनिक ओलंपिक खेल या ओलंपिक खेल, ग्रीष्म और शीतकालीन खेलों की विशेषता वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ शीर्ष खेल आयोजन जिनमें दुनिया भर से हजारों एथलीट शामिल होते हैं खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। ओलिंपिक खेलों इसे दुनिया का सबसे प्रमुख खेल आयोजन माना जाता है जहाँ 200 से अधिक राष्ट्रीयताएँ भाग लेती हैं। ओलिंपिक खेलों यह आमतौर पर हर चार साल में आयोजित किया जाता है चार साल की अवधि के दौरान हर दो साल में गर्मी और शीतकालीन ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया जाता है। मूलः ओलंपिक खेलों का निर्माण ईसा पूर्व चौथी और आठवीं शताब्दी के बीच हुआ था। ओलंपिया, ग्रीस में आयोजित एक प्राचीन उत्सव, जो 10वीं शताब्दी ई.पू. का है ओलिंपिक खेलों से प्रेरित थे। बैरी नीरे डे काउंटी 1894 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की, जो पहला आधुनिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया था। आईओसी ओलंपिक आंदोलन का शासी निकाय ओलंपिक समिति है, जो निम्न से बना हैः संरचना और अधिकार को परिभाषित करता है। पिकसः 20वीं और 21वीं सदी के वैश्विक आंदोलन वापसी से ओलंपिक खेलों में कई बदलाव आये है इस संयोजन में कुछ बर्फ और बर्फ के खेल शामिल हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेलों का निर्माण, एथलीटों की रिहाई अंतरराष्ट्रीय खेलों के लिए, 14 से 18 वर्ष की आयु के एथलीट युवा ओलंपिक खेलों और पांच महाद्वीपीय खेलों के लिए (सभी) अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और प्रशांत) और विश्व खेल जो सिर्फ़ ओलंपिक खेलों में ही नहीं खेले जाते। आईओसी डेर्नलनिक और निशेश ओलानिक का समर्थन करते हैं। प्रकारः 1. ग्रीष्मकालीन ओलंपिकः ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जिन्हें ओलंपियाड के खेल के रूप में भी जाना जाता है इसे आमतौर पर हर चार साल में एक बार भी जाना जाता है एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन आयोजित किया जा रहा है-है खेल पहली बार 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किए गए थे। हाल ही में 2021 में टोक्यो, जापान में आयोजित किया गया था हाँ। गर्मियों में पाँच महाद्वीपों पर कुल उन्नीस देश ओल्यानिक की मेजबानी की गई है। स्पोट्र्स यूएसए चार बार (1904, 1932, 1984 और 1996) , ग्रेट ब्रिटेन में तीसरा बार (1908, 1948 और 2012) , ग्रीस (1896 और 2004) , ंस (1900 और 1924) , जर्मनी (1936 और 1972) , ऑस्ट्रेलिया (1956 और 2000) और ब्राज़ील में दो (1964 और 2020) । इसका आयोजन कई बार किया जा चुका है। पिछली ग्रीष्म संक्रांति के ठीक बाद सौ साल बाद 2024 में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा। पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 2028 में आई.ओ.सी लॉस एंजिल्स अपने तीसरे ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी करेगा एंजेल्स, कैलिफ़ोर्निया और निस्बेल को भी चुना गया। क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया 2032 में अपने तीसरे ओलंपिक की मेजबानी करेगा. शीतकालीन ओलंपिक खेल बर्फ और बर्फ पर खेले जाते हैं खेल हर चार साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है। झुंड शीतकालीन ओलंपिक खेल, 1924 शीतकालीन ओलंपिक, यह फ्रांस के शैमॉनिक्स में आयोजित किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्राचीन ओलंपिक खेलों से प्रेरित थे, जो थे ओलिंपिक गेम्स में सबकुछ ओलानिया, ग्रीस, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक में आयोजित किया जाता है शीतकालीन ओलंपिक खेल तीन महाद्वीपों के 12 देश मेजबानी कर रहे हैं। अमेरिका में चार (1932, 1960, 1980 और 2002) बार, ग्रेट ब्रिटेन ने तीन बार (1908, 1948 और 2012), ग्रीस दो बार (1896 और 2004) फ्रांस तीन बार (1924, 1968 और 1992) और ऑस्ट्रिया (1964 - 1976) , इटली (1956 और 2006) , ब्राज़ील (1952 और 1994) और स्विट्जरलैंड में दो बार (1928 और 1948) आयोजित किया गया। यहाँ पैरालिंपिकः 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैनिकों की बस्ती 1948 में, सर लुईस कॉटमैन ने अभियान चलाने की ठानी कई अस्पताल लंदन ओलंपिक के अनुरूप है इसमें मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया जाता है। मूल स्वरूप जैसा कि इसे स्टोक मंडला गेम के नाम से जाना जाता है, कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक खेल महोत्सव में तब्दील हो गया। अगले 12 साल 2007 में, शुटमैन और अन्य ने खेल को चिकित्सा के रूप में वर्णित किया। ।1960 में 400 एथलीटों को रोम लाया गया जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे तब से हर वर्ष ओलम्पिक खेल आयोजित किये जाते रहे हैं। सियोल में 1988 के ग्रीष्मकालीन खेलों के बाद से आयोजित किया गया ये शुरू हुआ। 2010 में ओलंपिक खेलों की जगह युवा खेलों ने ले ली था, जिसने 14 से 18 वर्ष की आयु के एथलीटों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी थी। यूथ ओलंपिक गेम्स आईओसी का गढ़ है जैक्स रोगे, आईओसी के अध्यक्ष, 2001 में और आई.ओ.सी इसे 119वीं कांग्रेस के दौरान मंजूरी दी गई थी। ग्रीष्मकालीन युवा खेल 14 से 26 अगस्त 2010 तक सिंगापुर में आयोजित किए गए थे, जबकि शीतकालीन खेल दो साल बाद ऑस्ट्रिया में आयोजित किए गए थे। ग्रीष्मकालीन संस्करण बारह दिनों तक चलता है और शीतकालीन संस्करण नौ दिनों तक चलता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन में स्थित एक गैर-सरकारी खेल संगठन है। इसे स्विस आचार संहिता (अनुच्छेद 60-79) के तहत एक महासंघ के रूप में संगठित किया गया है। 1894 में नीयर डी कोबिनेट और डेमेंटी जोस निकोलस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापित, किया गया यह आधुनिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए ज़िम्मेदार प्राधिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और विश्वव्यापी ओलंपिक प्राधिकरण का शासी निकाय है, जो ओलंपिक खेलों में शामिल सभी संगठनों और व्यक्तियों के लिए शासी निकाय है। 2020 तक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हैं। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष जर्मनी के थॉमस बाक हैं, जिन्होंने सितंबर 2013 में बेल्जियम के जैक्स रोथ का स्थान लिया था। ओलंपिक चिन्ह, जिसे ओलंपिक रिंग के नाम से जाना जाता है इसमें पाँच परस्पर जुड़े हुए वलय हैं जो पाँच बसे हुए महाद्वीपों का निर्माण करते हैं। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया देशों चित्रित करने के लिए मैदान में हरा, काले, हरे और लाल छल्लों के रंग संस्करण झंडा फहराया गया प्रत्येक कारण से इन रंगों को चुना गया राष्ट्र के राष्ट्रीय ध्वज में इनमें से कम से कम एक रंग था। झंडा 1914 में लागू किया गया लेकिन बेस्टियम के अभिलेखागार में 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार जीता था तब से यह हर खेल आयोजन के दौरान खेला जाता है। ओलम्पिक खेलों का उद्घाटन ग्रीस के राजा जॉर्ज प्रथम के द्वारा 1896 में किया गया था।6 अप्रैल 1896 को, अमेरिकी जेम्स कोनोली ने ट्रिपल जंप जीतकर 1,500 से अधिक वर्षों में पहला ओलंपिक चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। ओलम्पिक खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका के नाम है।(लेखक - संजय गोस्वामी/ईएमएस)

जब तक महिला दोबारा शादी नहीं कर लेती, पा सकती है गुजारा भत्ता!

(चर्चा कानून की)

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मुस्लिम महिला ही नहीं, किसी भी धर्म की महिला भरण पोषण पाने की अधिकारी है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैंसले को मौलिक अधिकारों का हनन बताया है,हालांकि जो महिलाएं भरण पोषण से वंचित है,वास्तव में मौलिक अधिकार तो उनके प्रभावित हो रहे है। वोट की राजनीति के चलते अभी तक किसी भी दल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उक्त रुख का विरोध नही किया है। जबकि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैंसले का खुलकर समर्थन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वैसा ही फैसला दिया है, जैसा 23 अप्रैल सन 1985 को शाहबानो के भरण पोषण मुकदमे में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के निर्णय में कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार है। शाहबानो के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का फैसला दिया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर करने की हकदार है और वह अपने पूर्व पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त कर सकती है। सन1985 में भी सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में अपने फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सेक्युलर धारा है, जो सभी महिलाओं पर लागू होती है। इसके बाद सन 1986 में केंद्र सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार का संरक्षण) कानून पास कर इस फैसले को पलट दिया था। केस के तथ्यों में 15 नवंबर सन 2012 को पीड़ित मुस्लिम महिला ने अपने पति का घर छोड़ दिया था,सन 2017 में उक्त महिला ने अपने पति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 498 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे से नाराज होकर पति ने महिला को तीन तलाक दे दिया था,28 सितंबर सन 2017 को उनके तलाक का सर्टिफिकेट जारी हो गया। तलाक के बाद इद्दत की अवधि तक पति ने महिला को हर महीने 15 हजार रुपये का गुजारा भत्ता देने की पेशकश की, तलाक से तीन महीने तक होती है। लेकिन महिला ने तीन महीने के लिए गुजारा भत्ता लेने से इनकार कर दिया और फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने की मांग की। 9 जून सन 2023 को फैमिली कोर्ट ने हर महीने 20 हजार रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश उसके पूर्व पति को दिया। फैमिली कोर्ट के फैसले को पति ने तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी। 13 दिसंबर सन 2023 को हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा,लेकिन भरण पोषण की रकम 20 हजार से घटाकर 10 हजार रुपये कर दी।

पूर्व पति ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया व दलील दी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। मुस्लिम महिला पर सन 1986 का मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार का संरक्षण) कानून लागू होता है। उसने ये भी दलील दी सन 1986 का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 99 पन्नों का फैसला देते हुए कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर करने की हकदार है। क्योंकि सीआरपीसी की धारा 125 सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है, जिनमें शादीशुदा मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं,साथ ही सीआरपीसी की धारा 125 सभी गैर-मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती है। अगर किसी मुस्लिम महिला की शादी या तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है, तो भी उस पर धारा 125 लागू होगी,अगर मुस्लिम महिला की शादी और तलाक मुस्लिम कानून के तहत होता है तो उसपर धारा 125 के साथ-साथ सन 1986 के कानून के प्रावधान भी लागू होंगे। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पास दोनों कानूनों में से किसी एक या दोनों के तहत गुजारा भत्ता पाने का विकल्प है। अगर सन 1986 के कानून के साथ-साथ मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भी याचिका दायर करती है तो सन 1986 के कानून के प्रावधानों के तहत जारी हुए सीआरपीसी की धारा 127(3)( ) के तहत याचिका पर विचार किया जा सकता है। अगर पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिया गया है, तो धारा 127(3)( ) के तहत भी मजिस्ट्रेट विचार कर सकते हैं। चूंकि तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त सन 2017 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था, इसके बाद सन 2019 में केंद्र सरकार ने कानून लाकर तीन तलाक को न सिर्फ असंवैधानिक घोषित किया, बल्कि इसे अपराध के दायरे में भी शामिल कर दिया है। अपने फैसले में जस्टिस नागरत्ना ने माना कि तीन तलाक के अवैध तरीके से भी किसी मुस्लिम महिला को तलाक दिया जाता है तो वो भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा कर सकती है।

क्योंकि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 से बाहर नहीं रखा जा सकता, भले ही उसे किसी भी कानून के तहत तलाक दिया गया हो। सीआरपीसी की धारा 125 में महिलाओं, बच्चों और माता-पिता को मिलने वाले गुजारा भत्ता का प्रावधान है। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान धारा 144 में दिया गया है,जिसके अनुसार कोई भी पुरुष अलग होने की स्थिति में अपनी पत्नी, बच्चे और माता-पिता को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। धारा साफ करती है कि पत्नी, बच्चे और माता-पिता अगर अपना खर्चा नहीं उठा सकते तो पुरुष को उन्हें हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। पत्नी को गुजारा भत्ता तब मिलेगा जब या तो वो खुद तलाक ले या उसका पति तलाक दे, गुजारा भत्ता तब तक मिलेगा जब तक महिला दोबारा शादी नहीं कर लेती।

इस धारा में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है या किसी और पुरुष के साथ रहती है या फिर आपसी सहमति से अलग होती है तो वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी।

23 अप्रैल सन 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया था। शाहबानो इंदौर की रहने वाली थीं और उनके पति ने उन्हें तीन तलाक दे दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत शाहबानो अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। 1986 के इस कानून की धारा 3 में तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता का प्रावधान है। धारा 3 में लिखा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को पूर्व पति से इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता मिल सकता है। इद्दत की अवधि तीन महीने होती है। इसी धारा में ये भी लिखा है कि अगर तलाक से पहले या तलाक के बाद महिला अकेले बच्चे का पालन-पोषण नहीं कर सकती तो उसे दो साल तक पूर्व पति से गुजारा भत्ता मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारतीय पुरुष परिवार के लिए गृहिणी की भूमिका और त्याग को पहचानें। उन्हें संयुक्त खाते और एटीएम खोलकर उसे वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। महिलाओं के भरण पोषण पर एक बड़ी लकीर खींचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें धर्म बाधा नहीं है। कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी भरण पोषण के लिए पति की जिम्मेदारी तय की है। (लेखक- डॉ श्रीगोपाल नारसन / ईएमएस)

शब्द पहेली - 8071

बाएँ से दाएँ

1. शमशीर, कृपाण-4
4. उपद्रवी, आतंकी-4
6. अनुबंध, संधि-3
8. धोखा, छल, मक्कारी-3
9. चांदी-3
11. अश्रु-2
13. नीचता-5
15. कुंजी, जिससे ताला खोलते हैं-2
16. पुराना जुकाम-3
18. प्रश्न-3
19. चांदी-3
20. जहां ताजिये दफन किए जाते हैं-4
22. बोरिया-बिस्तर-4

ऊपर से नीचे

1. झगड़ा, कहासुनी-4
2. संगीत यंत्र-2
3. बहुत बड़ा, विशाल-3
4. अपनत्व, अपनापा-5
5. अनबन, झगड़ा-4
7. कपड़े धोनेवाला-3
10. तहजीबदार-5
12. अकस्मात, सहसा-4
14. दृष्टि, निगाह-3
17. बेमिसाल, अनूठा-4
18. बलवान-3
21. उम्मीद, आशा-2

शब्द पहेली -8070 का हल

आ	म	रा	य	■	सा	व	धा	न
रा	■	ह	म	स	फ	र	■	फ
ध	न	■	■	ली	■	■	का	र
ना	क	■	ना	का	रा	■	न	त
■	ब	हा	र	■	श	र	भ	■
खो	ज	■	द	ह	न	■	र	म
फ	न	■	■	र	■	■	ना	न
ना	■	स	र	फ	रो	श	■	ब
क	र	त	ब	■	ना	मा	व	ली

Jagrutidaur.com, Bangalore

सम्पादकीय

खेल - समाचार

केकेआर को अलविदा कहने के दौरान गंभीर ने दिया भावुक संदेश

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के नये मुख्य कोच बने गौतम गंभीर ने केकेआर को अलविदा कहने के दौरान एक भावुक संदेश अपने प्रशंसकों को दिया है। गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने दो बार आईपीए खिताब जीता था। वहीं इस साल उनके मेंटोर रहते हुए टीम ने तीसरी बार खिताब जीता। गंभीर ने केकेआर से विदा लेते हुए कहा, जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं भी मुस्कुराता हूं। वहीं जब आप रोते हैं तो मैं भी रोता हूं। जब आप की जीत होती है तो वो मेरी भी जीत होती है। वहीं जब आपकी हार होती है तो मैं भी हारता हूं।जब आप सपने देखते हैं तो मैं भी आपके साथ सपने देखता हूं. जब आप कुछ हासिल करते हैं तो उसमें भी मुझे सब मिलता है। मेरा विश्वास आपके साथ है और मैं आप बन जाता हूं, मैं आपका हूं कोलकाता। मैं आप में से ही एक हूं। साथ ही कहा, मैं आपके संघर्ष को जानता हूं और मुझे यह भी पता है कि चोट कैसी होती है। ठुकराए जाने पर मुझे भी आपकी तरह ही तकलीफ होती है लेकिन उम्मीदों को गले लगाकर में फिर उठ खड़ा होता हूं। मैं हर दिन हार का सामना करता हूं पर आपकी तरह कभी भी हारा नहीं। वे मुझे लोकप्रिय होने के लिए कहते हैं, मैं उन्हें विजेता बनने के लिए कहता हूं। मैं आपका हूं कोलकाता. मैं आप में से ही एक हूं।

गंभीर की श्रीलंका दौरे के लिए राष्ट्रीय चयन समिति के साथ हुई एक बैठक

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के नये मुख्य कोच गौतम गंभीर ने श्रीलंका दौरे के लिए तैयारियां शुरु कर दी हैं। इसी के तहत ही गंभीर ने राष्ट्रीय चयन समिति के साथ इस मामले पर बात की है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन हुई इस बैठक में श्रीलंका के खिलाफ टीम चयन पर बात हुई। इस बैठक में चयन समिति के सदस्यों के अलावा गंभीर और बीसीसीआई सचिव जय शामिल हुए। इस बैठक में अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को आराम दिए जाने पर भी बात हुई। इससे माना जा रहा है कि लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर की वापसी को सकती है। इसके अलावा केएल राहुल को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। राहुल को टी20 विश्व कप के लिए टीम में जगह नहीं मिली थी।

वहीं हार्दिक पांडया के एकदिवसीय सीरीज में नहीं खेलने के कारण केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव में से किसी एक को टीम की कप्तानी मिल सकती है। पांडया के बार-बार चोटिल होने को देखते हुए उनकी जगह राहुल को अवसर मिल सकता है। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान गंभीर ने बताया कि किस खिलाड़ी को वह टीम में चाहते हैं। भारत और के बची सीमित ओवरों की सीरीज 27 जुलाई से शुरू होगी। इसमें तीन एक दिवसीय और इतने ही टी 20 खेले जाएंगे।

इस साल श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगी

वेलिंगटन (ईएमएस)। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि इस साल श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम उसके यहां का दौरा करेंगी। इस दौरान सीमित ओवरों की एक सीरीज खेली जाएगी। इसके अलावा टीम इस साल के अंत में इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज की भी मेजबानी करेगी। न्यूजीलैंड की टीम नवंबर के अंत से लेकर अप्रैल की शुरुआत तक अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करेंगी। इसके तहत ही इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज 28 नवंबर को क्राइस्टचर्च में शुरू होगी। इसके अलावा वह श्रीलंका के खिलाफ एक सफेद गेंद की सीरीज और मार्च के मध्य में पाकिस्तान के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज खेलेगा।

न्यूजीलैंड की टीम का कार्यक्रम इस प्रकार बेहद व्यस्त रहेगा। उसकी टीम ने पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आयोजन से ठीक पहले फरवरी में दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज की पुष्टि की है।

श्रीलंका में एक पूर्व क्रिकेटर की गोली मारकर हत्या

कोलंबो (ईएमएस)। श्रीलंका में एक पूर्व क्रिकेटर धम्मिका निरोशन की गोली माकर हत्या कर दी गई है। धम्मिका की हत्या से लोगों में डर का माहौल है। 41 साल के धम्मिका अपने परिवार के साथ गॉल के अंबालांगोडा शहर में रहते थे। उनकी हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। इस क्रिकेटर को अपराधियों ने पत्नी और बच्चों के सामने ही गोली माकर कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस जांच में लगी है पर अभी तक उसे कोई कारण नहीं मिला है।

अंडर 19 क्रिकेट टीम टीम के कप्तान रहे धम्मिका को राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिल पायी थी। उन्होंने साल 2001 से 2004 के बीच गॉल क्रिकेट क्लब की तरफ से 12 फर्स्ट क्लास मैच और 8 लिस्ट ए मैच खेले थे। निरोशन ने अपने करियर में कुल 24 विकेट हासिल किए और 300 से ज्यादा रन बनाए.। साल 2000 में अंडर 19 टीम में डेब्यू किया था. दो साल बाद ही वह टीम के कप्तान भी बने थे। उन्होंने अंतिम बार साल 2004 में खेला था।

भारत के शौर्य को सेमीफाइनल में हार से मिला कांस्य

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत के शौर्य बावा को ह्यूस्टन में जारी विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में कांस्य पदक मिला है। शौर्य को एकल सेमीफाइनल में मिस्त्र के शीर्ष वरीयता प्राप्त मोहम्मद जकारिया ने 0-3 से हराया। जकारिया ने रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में शौर्य को 5-11 5-11 9-11 से हराया। शौर्य विश्व जूनियर सेमीफाइनल में पहुंचने वाले केवल दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं, इससे पहले साल 2014 में कुश कुमार यहां तक पहुंचे थे। शौर्य ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के लो वा सर्न को 3-2 से पराजित किया था। वहीं लड़कियों के वर्ग में भारत की अनाहत सिंह मिस्त्र की नादियां इल्हामामी के हाथों 11-8, 11-9, 5-11, 10-12, 13-11 से मिली हार से क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गयीं थी।

रोहित, विराट और बुमराह को छोड़कर अन्य सभी के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य : बीसीसीआई

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने कहा है कि कप्तान रोहित शर्मा , विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए खाली समय में घरेलू क्रिकेट खेलना जरुरी नहीं है। वहीं ने बोर्ड के नये नियम के अनुसार अन्य सभी खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बना पायेंगे। टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए हर एक खिलाड़ी के लिए कम से कम एक घरेलू मुकाबला खेलना जरुरी है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने गत वर्ष कहा था कि नये नियम के अनुसार सभी खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य है। साथ ही कहा था कि आईपीएल के लिए घरेलू क्रिकेट की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। साथ ही कहा कि जब खिलाड़ी अंतराष्ट्रीय सीरीज नहीं खेल रहे हों तो उन्हें अपनी घरेलू टीम की तरफ से मैच में खेलने के लिए उपलब्ध रहना होगा। पिछले साल श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट खेलने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद से ही ये दोनो टीम से बाहर हैं। इन्हें केन्द्रीय अनुबंध भी नहीं मिला है।

वहीं रोहित, विराट और बुमराह को बीसीसीआई की तरफ से जारी सूची से अलग रखा गया है। इसके आलावा जितने भी टीम में जगह बना चुके या बाहर बैठे खिलाड़ी हैं, सबके लिए बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि कम से कम एक घरेलू मैच तो खेलना होगा।

ओलंपिक में भारत को भाला फेंक, मुक्केबाजी और बैडमिंटन में अधिक पदकों की उम्मीद रहेगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत को 27 जुलाई से शुरु हो रहे पेरिस ओलंपिक में पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पिछले बार हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक स्वर्ण सहित कुल सात पदक मिले थे जबकि इस बार भारत को अधिक पदकों की उम्मीद रहेगी। इस बार भारतीय दल में 100 से अधिक खिलाड़ी शामिल हैं। भारत को मुक्केबाज , जैवलिन थ्रो, भारोत्तोलन और बैडमिंटन व हॉकी में पदक जीतने की उम्मीद है। इससे पहले टोक्यो में भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। इस बार भी उनका लक्ष्य स्वर्ण जीतना रहेगा। वहीं भारोत्तोलन में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में मीराबाई चानू पदक की दावेदारी पेश करेंगी। उन्होंने टोक्यो में रजत पदक जीता था। ऐसे में अब उनसे स्वर्ण की उम्मीद है। महिला बैडमिंटन स्टार पी.वी. सिंधु ने ओलंपिक में रजत और कांस्य पदक जीता है। इस बार उनका लक्ष्य स्वर्ण जीतना रहेगा। बैडमिंटन में एच.एस. प्रणय, लक्ष्य सेन समेत कई अन्य स्टार खिलाड़ी भी दल में शामिल हैं। ऐसे में भारत को बैडमिंटन में भी दो-तीन पदक की उम्मीद है। वहीं मुक्केबाजी की बात करें तो इसमें भारत का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। इस बार भारतीय दल से कम से कम दो-तीन पदकों की उम्मीद है। अनुभवी निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन सहित अमित पंघाल जैसे मुक्केबाज जीत के इरादे उतरेंगे। इसके अलावा मनु भाकर भी बेहतर प्रदर्शन का प्रयास करेंगी।

जन हितैषी

सकल जीडीपी को घटाकर 4.9-5.0 प्रतिशत कर सकती है सरकार

- रेटिंग एजेंसी इक्रा ने जताई यह संभावना

नई दिल्ली (ईएमएस)। राजस्व में आए उछाल के दम पर केंद्र सरकार अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.9-5.0 प्रतिशत कर सकती है। मंगलवार को रेटिंग एजेंसी इक्रा ने यह संभावना जताई। इस साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश करते समय सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। इक्रा रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, केंद्र सरकार 11.1 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय लक्ष्य से कोई समझौता किए बगैर राजकोषीय घाटा अनुमान को 5.1 प्रतिशत से घटाकर 4.9-5 प्रतिशत निर्धारित कर सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं। यह उनका लगातार सातवां बजट होगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी का 5.6 प्रतिशत राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल किया था। नायर ने कहा, 11.8 लाख करोड़ रुपए के अंतरिम बजट अनुमान की तुलना में चालू वित्त वर्ष के लिए शुद्ध बाजार उधारी में 35,000-55,000 करोड़ रुपए की कमी आने की भी बहुत संभावना है। यह जे पी मॉर्गन सरकारी बॉन्ड सूचकांक में शामिल किए जाने के कारण सरकारी प्रतिभूतियों की मांग को बढ़ावा देने के साथ प्रतिफल के लिए भी अच्छा संकेत होगा।

नायर ने कहा कि अगले तीन-चार वर्षों में राजकोषीय घाटे के व्यापक आकार में कमी लाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात में गिरावट काफी हद तक मौजूदा कीमतों में जीडीपी वृद्धि पर निर्भर करेगी।उन्होंने कहा कि 1.2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धिशील राजस्व प्राप्तियों को राजस्व व्यय बढ़ाने और राजकोषीय मजबूती के लिए विभाजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ आयकर छूट देकर खपत को बढ़ावा देने के लिए भी इसका उपयोग कर सकती है।

सेबी ला रहा नया प्रोडक्ट, निवेश के लिए लगाने होंगे 10 लाख, जोखिम भी होगा

नई दिल्ली,(ईएमएस)। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों को एक नए तरह का विकल्प लाने का प्रस्ताव दिया है, जो बाजार में जोखिम उठाकर ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। अभी पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं (पीएमएस) या वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) बहुत महंगे हैं। अभी सेबी ने इस नए प्रोडक्ट को नाम नहीं दिया है और इसमें निवेश के लिए कम से कम 10 लाख रुपए लगाने होंगे। यह सीमा पीएमएस (50 लाख) और एआईएफ (एक करोड़ रुपए) से काफी कम है। वहीं, म्यूचुअल फंड में तो सिर्फ 100 रुपए से भी निवेश शुरू किया जा सकता है।

सेबी का कहना है कि वह नए तरह का निवेश का तरीका लाना चाहता है। इसमें ज्यादा पैसा लगाना होगा और ज्यादा रिस्क भी उठाना होगा। ये इसलिए ताकि लोग जोखिम वाले गलत निवेश ना करें। नया तरीका ना तो म्यूचुअल फंड जैसा होगा ना ही प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट जैसा, बल्कि दोनों के बीच का रास्ता होगा। सेबी को लगता है कि अभी तक ऐसा कोई निवेश का तरीका नहीं है जिसमे थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा कमाई की जा सके।

इसी का फायदा उठाकर गलत लोग ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर लोगों को ठगते हैं। इसलिए सेबी नया निवेश ला रहा है। ये तरीका म्यूचुअल फंड जैसा होगा लेकिन थोड़ा ज्यादा जोखिम वाला। इसमें शेयर बाजार के कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल भी किया जाएगा जो आम तौर पर म्यूचुअल फंड में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयरों को गिरने से बचाने के लिए ही एक अलग तरह का दांव लगा सकते हैं। वहीं, नया तरीका सीधे शेयरों के ऊपर या नीचे जाने का दांव लगाने की इजाजत देगा। इससे ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन ज्यादा नुकसान का भी रिस्क है। इसी तरह, नए तरीके में सरकारी बॉन्ड या रीट और इनविट में निवेश की सीमाएं थोड़ी ढीली होंगी, मतलब आप इनमें थोड़ा ज्यादा पैसा लगा सकेंगे।

सेबी इस नए निवेश तरीके को म्यूचुअल फंड और बाकी निवेश विकल्पों से अलग दिखाना चाहता है ताकि लोग इसे गलत नहीं समझें। इस नए तरीके का एक अलग नाम होगा ताकि ये साफ हो कि ये ना तो म्यूचुअल फंड है और ना ही प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, एआईएफ, रीट या इनविट जैसा कोई दूसरा मौजूदा निवेश है। सेबी ने बताया है कि कौन सी कंपनियां इस नए निवेश तरीके की पेशकश कर सकती हैं। इसके लिए सिर्फ वही कंपनियां योग्य होंगी जो कम से कम तीन साल से बाजार में मौजूद हैं और जिनके पास 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। अगर कोई कंपनी इन शर्तों को पूरा नहीं करती तो भी वह कुछ और शर्तें पूरी करके आवेदन कर सकती है। इसके लिए उस कंपनी को मुख्य निवेश अधिकारी को नियुक्त करना होगा जिसके पास कम से कम 10 साल का फंड मैनेजमेंट का अनुभव हो और कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रबंधन करने का अनुभव हो। साथ ही उन्हें नए निवेश तरीके के लिए एक और फंड मैनेजर की नियुक्ति भी करनी होगी जिसके पास कम से कम साल साल का फंड मैनेजमेंट का अनुभव हो और कम से कम 3,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का प्रबंधन करने का अनुभव हो। सेबी ने इस नए निवेश के बारे में लोगों से छह अगस्त तक सुझाव मांगे हैं।

एडीबी ने भारत के जीडपी ग्रोथ रेट का अनुमान 7 प्रतिशत पर

नई दिल्ली (ईएमएस)। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की ग्रोथ रेट का अनुमान वित्त वर्ष 2025 के लिए 7 प्रतिशत पर स्थिर रखा। बैंक ने यह निर्णय औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत वृद्धि और आवास निर्माण में बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए लिया। एडीबी ने कहा, केंद्र सरकार की मजबूत वित्तीय स्थिति से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन, मौसम में बदलाव और भू-राजनीतिक झटकों से उत्पन्न जोखिमों को भी ध्यान में रखना होगा। एडीबी के जुलाई आउटलुक में कहा गया है कि सामान्य से बेहतर मानसून की भविष्यवाणी के साथ भारत का कृषि क्षेत्र फिर से मजबूत हो सकता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। एडीबी ने कहा, बैंक क्रेडिट मजबूत आवास मांग और निजी निवेश की मांग को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि, एक्सपोर्ट ग्रोथ सेवाओं द्वारा नेतृत्व करेगी, जबकि वस्त्र निर्यात अपेक्षाकृत कमजोर वृद्धि दिखाएंगे। वित्त वर्ष 2026 के लिए, एडीबी ने अपने अप्रैल आउटलुक में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 7.2 प्रतिशत पर स्थिर रखा है। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के अनंतिम अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो वित्त वर्ष 2023 में दर्ज 7 प्रतिशत से अधिक है। इस बढ़ोतरी का श्रेय चौथी तिमाही में अपेक्षा से अधिक 7.8 प्रतिशत विस्तार को जाता है।

दालों की कीमतों में आई गिरावट, रिटेल बाजार में नहीं घटे दाम, लोग परेशान

नई दिल्ली,(ईएमएस)। कई महीनों के बाद अब अरहर या तुअर और उड़द की दाल की थोक कीमतें घटी हैं। सरकार ने बताया कि इन दालों की कीमतों में करीब चार फीसदी की कमी आई है। इसके साथ ही उम्मीद थी कि अब खुदरा बाजार में भी कीमतें कम होंगी लेकिन, रिटेल बाजार में इन दालों की कीमत घटने के बजाय बढ़ गईं हैं। इसके बाद केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने देश के रिटेलरों के साथ बैठक की।

सरकार ने रिटेलरों को चेतावनी दी है कि थोक बाजार के अनुरूप ही खुदरा बाजार में भी कीमतें कम हो। बीते दिन सरकार ने रिलायंस रिटेल, डी मार्ट, टाटा स्टोर्स, स्पेंसर्स, आरएसपीजी, वी मार्ट जैसे बड़े रिटेलर्स के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने रिटेलर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दालों की कीमतें कम नहीं हुईं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पिछले कुछ दिनों से थोक मंडियों में तुअर, चना और उड़द जैसी दालों की कीमतों में मामूली गिरावट आई है लेकिन, रिटेल बाजार में कीमत कम नहीं हुई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक पिछले एक महीने में प्रमुख मंडियों में चना, तुअर और उड़द की कीमतों में 4फीसदी तक की गिरावट आई है, लेकिन खुदरा कीमतों में समान गिरावट नहीं देखी गई है।

भारत में ग्रीन सर्टिफाइड ए-ग्रेड ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ी, चेन्नई टॉप पर

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत में ग्रीन सर्टिफाइड ए-ग्रेड ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ रही है। इन ऑफिस की हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ रही है। ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस की हिस्सेदारी में चेन्नई टॉप पर है। इसके बाद एनसीआर का बाजार है। ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस का किराया भी ज्यादा है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सात प्रमुख शहरों में ए-ग्रेड ऑफिस के कुल स्टॉक में ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस की हिस्सेदारी बढ़कर 65 फीसदी हो गई। इस समय सात प्रमुख शहरों में ए-ग्रेड ऑफिस का कुल स्टॉक 88.85 करोड़ वर्गफुट है। इनमें से 57.77 करोड़ वर्गफुट यानी 65 फीसदी ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस हैं। भारत में 1,362 ए-ग्रेड ऑफिस में से 805 यानी 59 फीसदी ऑफिस ग्रीन सर्टिफाइड हैं। जो भारत के निर्माण के प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं । पांच लाख वर्गफुट से कम बिल्ड-अप एरिया वाली 47 फीसदी ऑफिस ग्रीन सर्टिफाइड हैं। दस लाख वर्गफुट से ज्यादा बिल्ड-अप के 19 फीसदी ऑफिस ही ग्रीन सर्टिफाइड है। एक लाख वर्गफुट से कम बिल्ड-अप वाली ऑफिस में ग्रीन सर्टिफिकेट बहुत ही कम हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऑफिस बाजार के लिए सात प्रमुख शहरों में ए-ग्रेड ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस की सबसे ज्यादा 83 फीसदी हिस्सेदारी चेन्नई में है। चेन्नई में ए-ग्रेड ऑफिस के कुल स्टॉक 8.26 करोड़ में 6.83 करोड़ वर्गफुट ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस हैं। इसके बाद एनसीआर के 12.97 करोड़ स्टॉक में से 70 फीसदी 9 करोड़ वर्गफुट स्टॉक ग्रीन सर्टिफाइड है। ऑफिस स्पेस के सबसे बड़े बाजार बेंगलूरु के कुल 27 करोड़ वर्गफुट स्टॉक का 64 फीसदी हिस्सा ग्रीन सर्टिफाइड है। हैदराबाद के कुल आफिस स्टॉक में ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस की हिस्सेदारी 63 फीसदी, कोलकाता में यह 62 फीसदी, मुंबई में 61 फीसदी, जबकि पुणे में सबसे कम 56 फीसदी है।

रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस के किराये पर बिना ग्रीन सर्टिफाइड से 12 से 14 फीसदी प्रीमियम ज्यादा है। जो बिल्डरों को इन बिल्डिंग को बनाने में निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है। बेंगलुरु 23 से 25 फीसदी प्रीमियम के साथ टॉप पर है। चेन्नई और हैदराबाद में यह प्रीमियम 12 से 14 फीसदी और 13 से 15 फीसदी है। मुंबई और पुणे में डेवलपर ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग के लिए बिना ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग की तुलना में 8 से 12 फीसदी प्रीमियम लेते हैं। कंपनियां पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने और कर्मचारियों की भलाई के लिए प्रीमियम का भुगतान करती हैं।

केंद्र सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी करने पर कर रही विचार

-एनएफसीएसआर ने कहा-मौजूदा नीतियां चीनी उद्योग के लिए बन रहीं समस्या

नई दिल्ली (ईएमएस)। उत्पादन लागत बढ़ने से परेशान चीनी मिलों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ (एनएफसीएसआर) ने सरकार से चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य बढ़ाकर 42 रुपए प्रति किलोग्राम करने की मांग कर रहा है। बढ़ती उत्पादन लागत के बीच मिलों को चालू रखने में मदद मिल सके।

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड के निदेशक ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय नहीं लेने से चीनी उद्योग में कम मुनाफा, कर्ज जैसी समस्याएं फिर से उत्पन्न हो सकती हैं। सरकार ने गन्ने का एफआरपी (उचित एवं लाभकारी मूल्य) तीन बार बढ़ाया है, लेकिन चीनी के एमएसपी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सभी राज्य महासंघ पांच साल से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी नीतियां चीनी उद्योग के लिए समस्या उत्पन्न कर रही हैं। हम सिर्फ चीनी उत्पादन की लागत की मांग कर रहे हैं। हम उत्पादन लागत के रूप में कम से कम 41 रुपए प्रति किलोग्राम चाहते हैं। गन्ने और परिवहन लागत बढ़ गई है और मजदूरी शुल्क भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन चीनी की कीमत वही है।

एनएफसीएसआर के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के निदेशक, पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिलों को लेकर अगले दस साल का रोड मैप तैयार किया है और चीनी उद्योग में आमूल-चूल परिवर्तन किये जायेंगे। गन्ने का एफआरपी बढ़ रहा है, इसकी तुलना में चीनी की कीमत नहीं बढ़ रही है। इसके कारण चीनी मिलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अगर चीनी उद्योग को बचाना है तो चीनी की न्यूनतम कीमत 4200 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में की गई है।

1951 में 12 ......2024 में 40 प्रतिशत पहुंच गई मुस्लिम आबादी

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा बयान

रांची (ईएमएस)। असम की डेमोग्राफी में हुए बदलाव को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि असम की डेमोग्राफी में आया बदलाव मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है। असम में मुस्लिम आबादी आज 40 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो 1951 में 12 प्रतिशत थी। सीएम सरमा ने चिंता जताकर कहा कि हमने कई जिले खो दिए हैं। यह मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है।

असम के सीएम सरमा रांची पहुंचे थे। इस दौरान सरमा ने दावा किया है कि झारखंड में कुछ माह बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी। सरमा झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हैं। वे पिछले एक महीने के भीतर तीसरी बार झारखंड आए हैं। उन्होंने कहा कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमें राज्य की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं-समर्थकों पर भरोसा है।

उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा सोरेन सरकार चुनाव के बाद सत्ता से बाहर होगी। सीएम सरमा ने कहा कि झारखंड आकर वह ऊर्जा से भर जाते हैं। वह यहां बार-बार आना चाहते हैं।

बता दें कि पार्टी की ओर से 5 जुलाई से राज्य के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तरीय नेताओं-कार्यकर्ताओं के अभिनंदन का कार्यक्रम हो रहा है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित पार्टी के सांसद-विधायक इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर चुनावी तैयारियों के टिप्स दे रहे हैं।

6 माह में 340 किमी दूर हिमाचल प्रदेश पर हाईकोर्ट नहीं पहुंचा ये संदेश

नई दिल्ली (ईएमएस)। शिमला में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 340 किमी दूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संवेदनशील संदेश 6 माह तक हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचे। इस दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कलीजियम (न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए समिति) से सलाह किए बिना, सुप्रीम कोर्ट को दो सीनियर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए गैर-योग्य होने के बारे में लिख दिया। ये दोनों अधिकारी पहले हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए सुझाए गए थे।

इसकी जानकारी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जे.के. शर्मा ने जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ के समक्ष पेश रिपोर्ट में दी। यह पीठ दो न्यायिक अधिकारियों, चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। इन दोनों का आरोप है कि हाई कोर्ट के कलीजियम ने सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम के 4 जनवरी के निर्देश को दरकिनार किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में उन्हें हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने के पिछले प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था। इसके बजाय हाई कोर्ट कलीजियम ने उनसे जूनियर न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति के लिए सिफारिश की थी।

रिपोर्ट में हाई कोर्ट ने कहा कि उसके मुख्य न्यायाधीश (सीजे) ने पिछले साल 11 दिसंबर को सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा की योग्यता के बारे में कोई और जानकारी चाहिए? लेकिन, 16 जनवरी को केंद्रीय कानून मंत्री ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम ने 4 जनवरी के अपने फैसले में सिंह और मल्होत्रा के नाम वापस हाई कोर्ट भेज दिए हैं, ताकि उन पर फिर से विचार हो सके। चौंकाने वाली बात ये है कि 6 महीने बाद भी हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम का 4 जनवरी का फैसला नहीं मिला। इसके बाद और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि हाई कोर्ट का कहना है कि कानून मंत्री के पत्र में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम के फैसले का उल्लेख था, ऐसा लगा कि ये फैसला सिर्फ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए था ताकि वे अकेले इन दोनों को जज बनाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर सकें।

इससे जजों की नियुक्ति के लिए कलीजियम प्रणाली की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई है। ये प्रणाली 1990 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के आधार पर बनी थी। इन फैसलों में बताया गया था कि हाई कोर्ट के कलीजियम में मुख्य न्यायाधीश और दो सबसे सीनियर जज शामिल होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के लिए, कलीजियम में मुख्य न्यायाधीश के साथ चार सबसे सीनियर जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए चयन करते हैं। हाई कोर्ट को शक था कि सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम ने सिंह और मल्होत्रा के नाम दोबारा विचार के लिए वापस भेजे हैं या नहीं, इसीलिए हाई कोर्ट ने बताया कि 27 फरवरी को सीजेआई ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हाई कोर्ट में जजों के पदों को भरने की याद दिलाई।

बहुत हो गया....... .मासिक धर्म अवकाश को लेकर नीति बनाए केंद्र

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत में अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश का मुद्दा फिर चर्चा में है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने आदेश में केंद्र को निर्देश दिया कि वे राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श कर महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक मॉडल नीति तैयार करे।

जामिया मिलिया इस्लामिया की मास्टर्स की एक छात्रा हर महीने मासिक धर्म अवकाश की वकालत करने वाली महिलाओं में से एक हैं। छात्रा बताती है कि उन्हें हर महीने मासिक धर्म यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पी.सी.ओ.एस.) की चुनौती से कैसे जूझना पड़ता है। वह बताती हैं पी.सी.ओ.एस. से होने वाला दर्द और तकलीफ बहुत ज्यादा हो सकती है। इसके बाद क्लास में जाना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना लगभग असंभव होता है।

एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 73 प्रतिशत महिलाएं चाहती हैं कि कंपनियां मासिक धर्म अवकाश की अनुमति दें। एक मार्केटिंग पेशेवर महिला ने बताया कि मासिक धर्म के दौरान दर्द और तकलीफ इतनी गंभीर होती है कि काम पर ध्यान केंद्रित करना असंभव होता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कुछ कंपनियों ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाए हैं। स्विगी ने बिना किसी सवाल के महीने में दो दिन मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है। स्विगी के अनुसार मासिक धर्म अवकाश या भुगतान किया गया अवकाश प्रदान करना उनके महिला कर्मचारियों की अनूठी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करता है, विशेष रूप से वे जो भोजन की डिलीवरी जैसी शारीरिक रूप से कठिन भूमिकाओं में लगी हुई हैं। स्विगी ने कहा कि जब हमने पहली बार मासिक धर्म अवकाश लागू किया, तब सकारात्मक प्रतिक्रिया में अचानक वृद्धि हुई।

पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र के तीन कानूनों की जांच के लिए विशेष समिति का गठन किया

कोलकाता (ईएमएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय न्याय संहिता सहित तीन कानूनों को राज्य में लागू करने से पहले उनकी जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। 7 सदस्यीय समिति इन कानूनों का गहन अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय होगा कि नए कानून राज्य में लागू किए जाएं या नहीं। 7 सदस्यीय समिति में असीम कुमार रॉय (रिटायर जस्टिस, कोलकाता हाई कोर्ट), मलय घटक, वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, एलडी एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता, संजय बसु, पश्चिम बंगाल पुलिस डीजी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल सदस्य बनाए गए हैं। इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 3 नए कानूनों को लागू करने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष कुछ मुद्दे उठाए थे, जिन पर केंद्र ने गौर नहीं किया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तीन कानूनों के महत्व और व्यापक निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए; राज्य सरकार एक समिति का गठन करना आवश्यक समझती है जो निम्नलिखित की जांच करेगी –

(1) तीन आपराधिक कानूनों में आवश्यकतानुसार राज्य-विशिष्ट संशोधनों का सुझाव दें।

(2) क्या राज्य स्तर पर आपराधिक कानूनों के नाम बदलने की आवश्यकता है?

(3) कोई अन्य मामला जिसे समिति आवश्यक समझे।

शरद पवार ने भतीजे अजित की एनसीपी में लगाई बड़ी सेंध

मुंबई (ईएमएस)। अजित पवार गुट से इस्तीफा देने के एक दिन बाद बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के कई नेता और पार्षद शरद पवार खेमे में लौट आए। पुणे में शरद पवार के आवास पर एनसीपी के पूर्व पिंपरी-चिंचवाड़ इकाई के प्रमुख अजीत गव्हाणे उन नेताओं में शामिल थे, जो उनके गुट में शामिल हुए। राकांपा की पिंपरी-चिंचवाड़ इकाई के तीन अन्य वरिष्ठ नेता- राहुल भोसले, पंकज भालेकर और यश साने- जिन्होंने मंगलवार को पार्टी छोड़ दी थी, वे भी संस्थापक खेमे में शामिल हो गए।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी (शरद पवार गुट) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार पिछले 60 वर्षों से महाराष्ट्र और केंद्र में विकास के लिए काम कर रहे हैं और यहां तक कि विपक्ष के लोग भी उनकी ओर बड़ी उम्मीद से देखते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि पार्टी में कई लोगों के अलग-अलग अनुभव हैं। हमने हमेशा सुनिश्चित किया है कि विकास की हमारी विचारधारा मजबूत रहे। पवार साहब (शरद पवार) पिछले 60 वर्षों से महाराष्ट्र और केंद्र में विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

एनसीपी (अजित पवार) नेता छगन भुजबल ने एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार से मुंबई में उनके आवास 'सिल्वर ओक' पर अचानक मुलाकात की।

कांगों में मिलिशिया के हमले में 72 लोगों की मौत

किंशासा,(ईएमएस)। पश्चिमी कांगो के एक गांव पर हथियारबंद हमलावारों के हमले में नौ सैनिकों और एक सैनिक की पत्नी समेत कम से कम 72 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि यहां टेके और याका समुदायों के बीच दो सालों से संघर्ष जारी है वह एक दूसरे पर आए दिन हमले करते रहत हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांगो की राजधानी किंशासा के पूरब में करीब 100 किलोमीटर दूर किन्सेले गांव में यह हमला हुआ। किन्सेले क्वामाउथ क्षेत्र में है जहां टेके और याका समुदायों के बीच दो सालों से संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में सैकड़ों आम नागरिक मारे जा चुके हैं। किन्सेले गांव पर हमला करने वाले लोग मोबोंडो मिलिशिया के सदस्य थे, जो खुद को याका समुदाय की रक्षा करने वाला बताते हैं।

चावल चोरी में भाजपा नेता गिरफ्तार

बंगलूरू (ईएमएस)। कर्नाटक भाजपा के नेता मणिकांत राठौड़ को चावल चोरी मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला कर्नाटक सरकार की अन्न भाग्य योजना से जुड़ा है। पुलिस ने कलबुर्गी शाहपुर स्थित आवास से भाजपा नेता को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इससे पहले मणिकांत टैगोर को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन भाजपा नेता पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे।

मणिकांत को 6077 क्विंटल चावल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। चोरी हुए चावल की कीमत दो करोड़ रुपये से ज्यादा थी।

यह चावल यादगिर जिले के एक सरकारी गोदाम से गायब हुआ था। राठौड़ ने साल 2023 में भाजपा के टिकट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अन्न भाग्य योजना के तहत कर्नाटक सरकार हर गरीब परिवार को हर महीने 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त देती है।

ओमान के तट पर पलटा तेल टैंकर, 13 भारतीय समेत 16 लापता

मस्कट(ईएमएस)। ओमान के समुद्र तट पर एक तेल टैंकर के पलटने से 13 भारतीयों सहित कुल 16 लोग लापता हैं। इनमें तीन श्रीलंका के भी है। ओमान के तट पर डूबे कोमोरोस ध्वज वाले तेल टैंकर के संबंध में समुद्री सुरक्षा केंद्र (एमएससी) ने डूबने की सूचना के एक दिन बाद यह जानकारी दी है। एमएससी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कोमोरोस के झंडे वाला एक तेल टैंकर रास मदरका से 25 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में डुकम के बंदरगाह शहर के पास पलट गया।

आपको बता दें कि डुकम का बंदरगाह ओमान के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित है, जो प्रमुख तेल और गैस खनन परियोजनाओं के करीब है। इनमें एक प्रमुख तेल रिफाइनरी भी शामिल है जो डुकम के विशाल औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है। यह ओमान की सबसे बड़ी एकल आर्थिक परियोजना है।

शंभू बॉर्डर खोलने की डेडलाइन खत्म ,किसान करेंगे दिल्ली कूच, 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च

चंडीगढ़ (ईएमएस)। पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर को खोलने के हाईकोर्ट के आदेश की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अभी तक बॉर्डर को खोलने की कोई पहल सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।

वहीं फरवरी से डटे किसानों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली कूच का एलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सदस्य जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वह शंभू सीमा खुलते ही दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी फैसला लिया गया है। यह ट्रैक्टर मार्च देश भर में निकाला जाएगा।

नई मांग नहीं, वादे पूरा करे सरकार

किसान आंदोलन के दौरान वाटर कैनन बॉय के नाम से मशहूर हुए नवदीप जलबेड़ा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद किसान नेताओं ने बुधवार को अंबाला एसपी कार्यालय के घेराव का फैसला टाल दिया है। डल्लेवाल ने बताया कि उनके पास छह महीने का राशन है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि उनको जंतर-मंतर या दिल्ली के रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर रास्ते में कहीं भी सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो वे वहीं पर धरना शुरू कर देंगे।

इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की होगी। डल्लेवाल ने कहा कि वे यह कूच ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ करेंगे, क्योंकि बारिश, गर्मी व सर्दी से बचने के लिए उनके पास एकमात्र विकल्प ट्रॉली ही होती है। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार से कोई मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार ने जो वादे किए थे, उनको पूरा करवाने के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बॉर्डर खोलने के लिए तैयार नहीं हो रही है। हरियाणा सरकार के रास्ता न खोलने पर व्यापारियों को भी किसानों का साथ देने के साथ भाजपा के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। 300 मीटर पंजाब की तरफ बॉर्डर का एरिया पड़ता है, इसलिए बॉर्डर खोलने का आदेश पंजाब सरकार के लिए भी है।

22 जुलाई को दिल्ली में होगा सम्मेलन

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) एवं किसान मजदूर मोर्चा का साझा सम्मेलन नई दिल्ली में 22 जुलाई को होगा। दोनों मोर्चों ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात के लिए पत्र लिखा है और उनसे मुलाकात करके संसद के आगामी सत्र में एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों की तमाम मांगों पर प्राइवेट बिल लाने की मांग की जाएगी। आने वाले दिनों में हरियाणा में घर-घर जाकर दोनों मोर्चों के पदाधिकारी किसानों व मजदूरों को जागरूक करेंगे। 15 सितंबर को हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर की किसान महापंचायत की जाएगी, जिसमें लाखों किसान शामिल होंगे।

अंबाला की जिला उपायुक्त डॉ. शालीन ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगा दी है। इन आदेशों के तहत पांच या इससे ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। एसपी कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में भीड़ एकत्रित नहीं हो सकेगी। ये आदेश 17 जुलाई से आगामी दो माह तक लागू रहेंगे। दातासिंहवाला बॉर्डर पर किसानों की सक्रियता बढ़ने लगी है। 17 और 18 जुलाई के अंबाला एसपी कार्यालय के घेराव को लेकर पंजाब के बठिंडा व सिरसा से एक हजार किसानों का जत्था पहुंच चुका है। इसके अलावा और भी किसान आ रहे हैं।

नवीन पटनायक ने बनाई शेडो कैबिनेट, विभागों की गतिविधियों पर रखेगी नजर

भुवनेश्वर (ईएमएस)। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने अपने 50 विधायकों को शेडो कैबिनेट बनाकर विभिन्न विभाग सौंपे हैं। ये विधायक इन विभागों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखेंगे और राज्य विधानसभा में विभागों से संबंधित मुद्दे उठाएंगे। बीजू जनता दल का कहना है कि इस काम का लक्ष्य विधानसभा में भाजपा सरकार को मजबूत जवाब देना है। यह अपने आप में एक अच्छी शुरूआत कही जा सकती है। पीएम मोदी खुद कई बार विपक्ष को सकारात्मक होने और सकारात्मक सुझाव देने का संसद में आह्वान कर चुके हैं।

राज्य में 24 साल तक शासन करने वाली बीजू जनता दल (बीजद) हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा के हाथों सत्ता खो बैठी थी। बीजद ने 147 सदस्यीय विधानसभा में 51 सीट जीती थी। वह ओडिशा में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। इसके बाद कयास लग रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ओडिशा विधानसभा में नेता विपक्ष का दायित्व स्वीकार कर लिया। आम तौर पर इतने साल मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले नेता विपक्ष के नेता का पद नहीं स्वीकार करते लेकिन नवीन पटनायक ने ऐसा कर एक नई मिसाल कायम की।

कर्नाटक में डेंगू का कहर,8 की मौत

बेंगलुरु (ईएमएस)। कर्नाटक में डेंगू बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। 10000 से ज्यादा डेंगू के मरीज जांच में पाए गए हैं। इनमें से कई गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है।

कर्नाटक में एक ही दिन में 487 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। इनमें से 128 मरीजों को अस्पतालों में भर्ती किया गया है। जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। अभी कर्नाटक के अस्पतालों में 358 मरीज भर्ती हैं।

इस वर्ष डेंगू के आठ मरीजों की मौत हो चुकी है।हासन और शिव मोगा में 2-2, धारवाड़, हावेरी,मैसूरू और बीबीएमपी में एक एक मरीज की मौत हुई है।डेंगू का सबसे ज्यादा कहर चिकमगलूर, मैसुरू, हावेरी, मांडया तथा धारवाड़ जिलों में देखने को मिला है। राज्य शासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू के रोकथाम के लिए विशेष प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।

अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की नियमित जमानत पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। अदालत ने कहा की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते है। फैसला लिखने में 5-7 का वक्त मिलेगा। इस बीच सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के बीच अदालत में तीखी बहस हुई। सीबीआई ने जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत का जोरदार विरोध किया वहीं सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं।

भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा बंद करो सबका साथ, सबका विकास ,अब जो देगा साथ सिर्फ उसका होगा विकास

कोलकाता (ईएमएस)। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बैठक में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रवादी मुस्लिमों की बात करता था और आपने भी नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा। इसकी जगह मैं कहूंगा कि जो हमारे साथ, हम उनके साथ। बंद करिए ये सबका साथ, सबका विकास का नारा। हमें अल्पसंख्यक मोर्चे की भी जरूरत नहीं है।

भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने जय श्री राम के नारे लगाए और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को छह सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 12 पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए शुभेंदु अधिकारी भी लोगों के निशाने पर हैं क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि टिकट बंटवारे में शुभेंदु अधिकारी को काफी तवज्जो दी गई थी।

चुनाव के बाद टीएमसी पर लगातार हमले कर रहे शुभेंदु अधिकारी

लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी ने राज्य में शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। साथ ही हाल ही में बंगाल में चार सीटों पर हुए उपचुनाव में भी टीएमसी ने जीत दर्ज की। इसके बाद से ही शुभेंदु अधिकारी टीएमसी पर खासे हमलावर हैं। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव और हालिया उपचुनाव में 50 लाख हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में लोकतंत्र मर चुका है। अधिकारी ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिस पर वो लोग पंजीकरण कर सकते हैं, जिन्हें वोट नहीं देने दिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने इन लोगों के लिए कानूनी लड़ाई लडऩे का भी एलान किया है।

संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से एक और बच्ची की मौत, अब तक 10 बच्चों को निगल चुका है

गांधीनगर (ईएमएस) राज्य में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से एक और बच्ची की मौत की खबर सामने आई हैं गांधीनगर जिले के देहगाम तहसील के अमराजी मुवाडा की 7 वर्षीय बच्ची की उपचार के दौरान मौत हो गई फिलहाल राज्य में 15 से अधिक संदिग्ध चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध मामले सामने आए हैं और उसमें 10 जितने बच्चों की मौत हो चुकी हैं इससे पहले आज अहमदाबाद के असारवा सिविल अस्पताल में उपचाराधीन मेहसाणा के एक बच्चे की मौत हो गई थी असारवा सिविल अस्पताल में अब भी 5 बच्चों का उपचार चल रहा हैं

अहमदाबाद के चांदलोडिया के एक और आंबावाडी के एक बच्चे को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं बता दें कि यह वायरस सबसे अधिक 9 महीने से लेकर 14 वर्षीय बच्चों को दिखाई देता हैं राज्य में अब तक 10 बच्चों की इस संदिग्ध रोग से मौत हो चुकी हैं राज्य के पंचमहल, मेहसाणा, अरवल्ली, साबरकांठा और महीसागर में इस वायरस के लक्षण देखने को मिल रहे हैं इन जिलों में कई बच्चों का उपचार चल रहा हैं राज्य में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने लोगों से सचेत रहने की अपील की हैं बच्चों को सीधे अपनी चपेट में लेनेवाला इस वायरस को लेकर राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में हैं राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि इस मामले में कई सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चों की मौत की वजह सामने आएगी

गुजरात में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में वायरल की पुष्टि से पहले दो और बच्चों की मौत हो गई है। राज्य में अभी तक आठ बच्चों की मौत हो चुका है। सरकार ने अभी तक चांदीपुरा वायरस की पुष्टि नहीं की है।

गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दो और मौतें होने की पुष्टि करते हुए बताया कि राज्य में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से मंगलवार को दो और मौतें होने की पुष्टि हो गई, जिससे राज्य वायरस से मरने वालों की संख्या आठ हो गई है। पटेल ने राज्य की राजधानी गांधीनगर में संवाददाताओं को बताया कि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 14 हो गई है, जिसमें से आठ लोगों की मौत हो चुकी है।

गुजरात में बड़े बदलाव कर सकती है बीजेपी, जानें आठ बड़े कारण

अहमदाबादः उत्तर प्रदेश में बदलाव की अटकलें के बीच बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में बड़ी सर्जरी की संभावना है। गुजरात में पिछले काफी समय से सरकार और संगठन में फेरबदल लंबित है। बीजेपी 15 अगस्त तक राज्य में कई नए बदलाव कर सकती है, ताकि राज्य में कांग्रेस के मजबूत होने की चुनौती का सही से मुकाबला किया जा सके। लोकसभा में विपक्ष के नेता बने राहुल गांधी ने 2027 में गुजरात में हराने की चुनौती फेंकी है। गुजरात विधानसभा में बीजेपी का संख्याबल 180 सीटों में 161 का है। सूत्रों की मानें तो केंद्रीय नेतृत्व संगठन के साथ सरकार में जरूरी बदलाव कर सकता है। गुजरात बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल अब केंद्र में मंत्री हैं। वह पहले ही एक पद और एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार जिम्मेदारी से मुक्त करने की अपील कर चुके हैं। इसके साथ ही संगठन में कई बड़े पद खाली पड़े हैं। कैबिनेट में फेरबदल होने पर कांग्रेस से आए अर्जुन मोढवाडिया से जैसे बड़े नेताओं को मंत्रीपद मिल सकता है। अब देखना है यह कि बीजेपी कांग्रेस से आए कितने नेताओं को मंत्री बनाती है।

गुजरात विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद राज्य के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। पिछले कई मौकों पर चर्चाएं आगे नहीं बढ़ पाईं, लेकिन लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद जब पार्टी के गुजरात नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी की दिशा में बढ़ रही है तब चर्चा है कि बीजेपी एक झटके में संगठन और सरकार दोनों में बदलाव कर सकती है।

गुजरात में भूपेंद्र पटेल सितंबर महीने में बतौर मुख्यमंत्री तीन साल पूरे करेंगे। पार्टी ने 2022 के चुनावों को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को फेस बनाकर जीता था। पार्टी ने 156 सीटें मिली थीं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के ऊपर करीब तीन साल के कार्यक्रम में व्यक्तिगत तौर पर कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन राज्य में पिछले तीन सालों में हुए तीन बड़े हादसों ने उनके लिए चुनौती खड़ी की है। मोरबी,हरनी और राजकोट हादसों में स्थनीय निकाय जिस तरह से कठघरे में खड़े हुए हैं। उसने उनकी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। इन मामलों में सरकार ने कार्रवाई की है लेकिन सरकार की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं। उससे बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार की किरकिरी हुई। राज्य में मजबूत सरकार होने के बाद भी लोगों के बीच प्रशासन में चुस्ती नहीं दिख पाई है, जिसकी अपेक्षा लोगों ने की थी। ऐसे में मुमकिन है बीजेपी संगठन के साथ सरकार में बड़े बदलाव करे और कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो जाए।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का एक महत्वपूर्ण निर्णय

६८८ किलोमीटर की ६५ सड़कों का उन्नयन-मजबूतीकरण किया जायेगा

राज्य के औद्योगिक और खनन क्षेत्रों के सड़क बुनियादी ढांचे के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 1470 करोड़ रुपए के आवंटन को दी सैद्धांतिक स्वीकृति

गांधीनगर 17 जुलाई : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे के विकास की मंशा के साथ औद्योगिक एवं खनन क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 1470 करोड़ रुपए के आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य से उद्योग एवं खान विभाग के साथ परामर्श कर उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में लेने का अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है। औद्योगिक एवं खनन क्षेत्रों को जोड़ने वाली इन सड़कों का विकास होने से इनसे जुड़े शहरों, नगरों और गांवों का यातायात सुगम बनेगा और परिवहन के लायक बेहतर सड़कों की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

उल्लेखनीय है कि गुजरात देश के सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्रों वाले राज्यों में एक अग्रणी राज्य है। इतना ही नहीं, पॉलिसी ड्रिवन स्टेट, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के परिणामस्वरूप गुजरात देश में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल करने वाले राज्यों में से एक बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में शुरू हुई वाइब्रेंट ग्लोबल समिट के फलस्वरूप राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग आने के कारण राज्य का असाधारण औद्योगिक विकास हुआ है।

ऐसे उद्योगों के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों को प्रोत्साहन देने के प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सड़क नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पिछले दो वर्षों में सड़क क्षेत्र के वित्तीय आवंटन में 80 फीसदी से अधिक की वृद्धि करने की पहल की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस संदर्भ में औद्योगिक एवं खनन क्षेत्रों को जोड़ने वाली कुल 688 किलोमीटर लंबाई की 65 सड़कों के लिए 1470 करोड़ रुपए आवंटित करने की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की है।

इस आवंटन के अंतर्गत 83 किलोमीटर सड़कों को फोरलेन तक चौड़ा करने के साथ ही 173 किलोमीटर सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इस कार्य के साथ-साथ 432 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का मजबूतीकरण किया जाएगा तथा पुलों और क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं का आवश्यक सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होने के बाद आवश्यकतानुसार इन सड़कों पर फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे।

इस निर्णय की पृष्ठभूमि में इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि खनन क्षेत्रों तथा उद्योगों को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों के अधिक सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ीकरण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सड़क एवं भवन विभाग को राज्य के सभी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं खनन क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों को ध्यान में रखकर उत्तर, मध्य, दक्षिण तथा कच्छ एवं सौराष्ट्र क्षेत्रों के समग्र विकास की रणनीति के अनुसार सड़कों को कवर करने के दिशानिर्देश दिए हैं।

यह आयोजन वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही उद्योग एवं खनन क्षेत्रों तथा उन्हें जोड़ने वाली सड़कों से जुड़े गांवों, नगरों और शहरों की भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। सड़कों के मजबूतीकरण और उन्नयन के लिए वित्तीय आवंटन की मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इस सैद्धांतिक अनुमति के चलते भविष्य में उद्योगों के लिए कच्चे माल, तैयार उत्पादों तथा मुख्य एवं गौण खनिजों की आवाजाही के और अधिक सुगम होने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी।

गुजरात के साथ शिक्षा, शोध समेत सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने को जापान उत्सुक

गांधीनगर (ईएमएस) जापान के शिजुओका प्रिफेक्चर (प्रांत) के 18 सदस्यीय शिष्टमंडल ने बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की। जापान की शिजुओका प्रांतीय असेंबली के सदस्य और वहां की असेंबली के इंडिया-जापान फ्रेंडशिप पार्लियामेंट लीग के महासचिव आत्सुयुकी राची के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल गुजरात के दौरे पर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ इस शिष्टाचार मुलाकात बैठक में उन्होंने गुजरात के साथ वाणिज्यिक संबंधों के अलावा पीपल टू पीपल कनेक्ट, शिक्षा, शोध, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों के सेतु को दीर्घकाल तक सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की उत्सुकता दिखाई। उन्होंने बताया कि जापान में 'मेक इन जापान' उद्योगों के अंतर्गत शिजुओका प्रांत का चौथा महत्वपूर्ण स्थान है। इतना ही नहीं, शिजुओका प्रांत में सुजुकी, यामाहा, होंडा और टोयोटा जैसे ऑटोमोबाइल उद्योगों का विशेष महत्व है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जापानी शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत-जापान के संबंध एक विश्वसनीय मित्र देश के रूप में आगे बढ़े हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात इन द्विपक्षीय संबंधों को और भी आगे ले जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जिस तरह 'मेड इन जापान' की विश्वसनीयता है, उसी तरह 'जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट' मंत्र के साथ 'मेक इन इंडिया' भी पर्यावरण अनुकूल और विश्वस्तरीय उत्पादों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने गुजरात में संचालित जापानी उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की मंशा व्यक्त करते हुए कहा कि उद्योगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध निरंतर आगे बढ़ते रहें, इसके लिए सरकार का दृष्टिकोण सक्रिय है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में बतौर पार्टनर कंट्री जापान के योगदान एवं सहयोग की भी सराहना की।

शिष्टमंडल के प्रमुख आत्सुयुकी राची ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को जापान और उनके प्रांत के दौरे पर आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में उनके प्रांत के गवर्नर भी भारत और गुजरात के दौरे पर आने को उत्सुक हैं। उन्होंने गुजरात-शिजुओका के संबंधों के सेतु को और अधिक फलदायी बनाने के लिए व्यापार-उद्योग क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने की तत्परता भी दिखाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल के प्रमुख आत्सुयुकी राची को स्मृति चिन्ह के रूप में कच्छी हस्तकला कारीगरों द्वारा तैयार कृति भेंट की।

अल्टो कार पलटने के बाद उसमें लगी आग, चालक की मौत

पाटन (ईएमएस) उत्तरी गुजरात के पाटन से दर्दनाक खबर सामने आई हैं पाटन जिले में राधनपुर-वाराही हाईवे पर एक कार में आग लग गई इस घटना में कार के साथ उसके चालक की भी जलकर मौत हो गई यह घटना पाटन जिले के मोटी पीपली गांव के निकट हुई जहां अल्टो कारण अचानक पलटी खा गई और उसके बाद कार में आग भड़क उठी चालक कुछ समझ पाता उससे पहले आग ने उसे भी अपनी आगोश में ले लिया इस घटना में कार चालक की मौत हो गई

लॉ गार्डन के निकट आंगडियाकर्मियों से 40 लाख की लूट के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद (ईएमएस) शहर के एलिस ब्रिज क्षेत्र के लॉ गार्डन के निकट हुई 40 लाख रुपए की लूट के मामले में क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया साथ ही आरोपियों के पास से रु. 36 लाख की नकदी भी बरामद कर ली यह घटना गत 10 जुलाई को उस वक्त हुई थी, जब अहमदाबाद के सीजी रोड स्थित आर कांतिलाल आंगडिया फर्म के दो कर्मचारी शहर के जमालपुर एपीएमसी से लाखों रुपए लेकर ऑटो रिक्शा में अपनी ऑफीस की ओर जा रहे थे

उस वक्त एक्टिवा पर आए दो शख्सों ने आंगडियाकर्मियों की आंखों में मिर्च छिड़क दी और 40 लाख रुपये कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे हांलाकि आरोपी पास के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए। पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश तेज कर दी और एक सप्ताह के भीतर सफलता भी हासिल कर ली अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों जफर इकबाल नियाज अहमद रंगरेज और मोहम्मद जावेद उर्फ जब्बो मोहम्मद हनीफ रंगरेज को गिरफ्तार कर लिया हैं पुलिस की प्रारंभिक जांच और आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपियों ने आंगडिया लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए रिवरफ्रंट रविवारी मार्केट से एक सफेद रंग की गाड़ी चुराई थी और उस पर स्प्रे पेंट से काला रंग कर उसमें गलत नंबर प्लेट लगाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था लूट की वारदात को अंजाम देते समय जो एयरगन अंगड़िया कर्मचारियों को दिखाई गई थी, उसे भी आरोपी जावेद ने कुछ समय पहले ऑनलाइन ऑर्डर किया था। लूट की घटना को अंजाम देने से एक दिन पहले यानी 9 जुलाई को दोनों आरोपियों ने इसका प्रयास किया था लेकिन ऐन मौके पर एक्टिवा चालू नहीं होने के कारण लूट की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए आरोपियों से पूछताछ यह भी खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी पिछले तीन महीने से जमालपुर पुल के नीचे खड़े होकर लूट की घटना को अंजाम देने के लिए रेकी कर रहे थे आंगड़िया फर्म के कौन से कर्मचारी किस गाड़ी में आए और किस गाड़ी में पैसे लेकर लौटे, इसकी रेकी भी इन दोनों ने की थी। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फतेवाडी इलाके में पहुंचे और लूट के वक्त पहने हुए कपड़े बदल कर एक्टिवा की डेकी में रख दिए जिसके बाद दोनों आरोपी अलग-अलग ऑटो रिक्शा से अपने-अपने घर पहुंचे। दोनों आरोपियों ने अपने घर तक पहुंचने के लिए दो बार रिक्शा बदला और सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए थोड़ी दूर पर रिक्शे से उतर जाते थे। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि जनवरी 2023 में भी दोनों आरोपियों ने एक लूट की घटना को अंजाम दिया था जिसमें जमालपुर इलाके में आंगड़िया फर्म के कर्मचारी को लकड़ी से मारकर 28 लाख की लूट चलाई थी इस घटना को अंजाम देने उपयोग की गई एक्टिवा भी आरोपी ने रिवरफ्रंट रविवारी बाजार से चोरी की थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हैं और 40 लाख रुपये में से करीब 36 लाख रुपये कैश जब्त कर लिया हैं आरोपी मोहम्मद ने 5 लाख रुपये में से 3 लाख रुपये से अपना कर्ज चुकाया और एक लाख रुपये अपने साथी जफर को दे दिए आरोपियों ने एक्टिवा चोरी, 2 लूट समेत कुल 3 घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की हैं

11 साल के किशोर की अपहरण के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार

बनासकांठा (ईएमएस) जिले के टोकरिया गांव 11 वर्षीय किशोर का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या की गई और उसका शव गांव की सीमा पर फैंक दिया गया इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई बच्चे की हत्या के बाद हरकत में आई पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया पूछताछ में आरोपी ने बच्चे की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया हैं जानकारी के मुताबिक बनासकांठा जिले की पालनपुर तहसील के टोकरिया गांव में रहनेवाले मुस्लिम परिवार के 11 वर्षीय मोहमद शेरसिया नामक किशोर का उसी गांव में रहनेवाले फारुक जमाल दाउमा नामक शख्स ने अपनी गाड़ी में अपहरण कर लिया अपहरण के बाद फारुक जमाल किशोर अलग अलग जगहों पर ले गया और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगा किशोर ने फारुक की गंदी हरकतों का विरोध किया तो उसे फारुक धमकाने लगा साथ ही उसे डर लगने लगा कि किशोर अपने परिजनों से शिकायत कर सकता हैं इसी डर में फारुक जमाल ने किशोर की हत्या कर दी और उसकी लाश गांव की सीमा पर फैंक दी दूसरी ओर मोहमद शेरसिया की तलाश कर रहे परिजनों को जब उसकी लाश मिली तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी किशोर की हत्या के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 10 जितनी अलग अलग टीमें बनाईं और टोकरिया गांव में पूछताछ शुरू कर दी उस दौरान संदेह के आधार पर फारुक जमाल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की शुरुआत में टालमटोल कर रहा फारुक जमाल पुलिस की सख्ती के आगे टूट गया और मोहमद शेरसिया की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया

भारतीय रेल ट्रेनों में स्वच्छता और परिचालन अनुशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध

अहमदाबाद (ईएमएस) पश्चिम रेलवे अपने सम्मानीय ग्राहकों को बेहतर सेवा सुनिश्चित करके स्वच्छ यात्रा परिवेश प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में ट्रेनों में सफाई बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए स्वच्छ ट्रेन स्टेशन और ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाएं जैसी व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा के दौरान पेंट्रीकार से निकलने वाले कचरे को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर गार्बेज कलेक्शटन प्वातइंट भी बनाए गए हैं, ताकि न केवल ट्रेनें और रेलवे परिसर साफ रहें, बल्कि रेलवे पटरियों के किनारे भी सफाई बनी रहे। इन अभियानों से स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित होता है जो ट्रेन यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाता है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लंबी दूरी की ट्रेनों की सफाई उन स्टेशनों पर की जाती है, जहां प्राथमिक रखरखाव किया जाता है। मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, रतलाम, भावनगर, वडोदरा, आदि। इस पहल के अंतर्गत पश्चिम रेलवे में लगभग 600 ट्रेनों की सफाई की जाती है तथा ट्रेन की सफाई के दौरान एकत्रित सभी कचरे का नियमानुसार निस्ताकरण किया जाता है। पश्चिम रेलवे के 24 स्टेशनों पर पेंट्री कार से कचरा संग्रह किया जाता है, जहाँ 77600 किलोग्राम कचरा (सूखा और गीला कचरा सहित) पेंट्री कार से एकत्र किए जाते हैं औरनियमों केअनुसार अंतिम निस्तााारण के लिए संबंधित प्रबंधक द्वारा रसीद पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। पश्चिम रेलवे की कुल 175 ट्रेनों में ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाएँ हैं। भारतीय रेल सभी ट्रेनोंमेंस्वच्छता और परिचालन अनुशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रियों और हितधारकों को तत्काल निवारण के लिए ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है,

अगले 48 घंटों के दौरान सौराष्ट्र के पांच जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात के विभिन्न हिस्सों में जारी बारिश के बीच मौसम विभाग से नई खबर सामने आई हैं जिसके मुताबिक आगामी 48 घंटों के दौरान राजकोट समेत सौराष्ट्र के पांच जिलों में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती हैं जिसे देखते हुए इन पांच जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया हैं साथ ही मछुआरों को अगले चार दिन समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई हैं मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में बारिश की चार सिस्टम सक्रिय हैं। इन सभी चार सिस्टम के कारण गुजरात में व्यापक बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र के कुछ जिलों में दो दिनों तक बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई हैं अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, द्वारका, राजकोट में आज बहुत भारी बारिश का अनुमान हैं इसके साथ ही सौराष्ट्र के बाकी सभी जिलों के अलावा दक्षिण गुजरात सूरत, नवसारी, वलसाड, उत्तरी गुजरात के बनास कांठा, साबरकांठा, अरवल्ली इत्यादि में ऑरेंज अलर्ट दिया गया हैं कल भी सौराष्ट्र के राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका और जाम नगर में अतिभारी बारिश की संभावना हैं जबकि अमरेली, भावनगर, बोटाद, गिर सोमनाथ, सुरेन्द्रनगर, मोरबी के अलावा दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया हैं वहीं 19 जुलाई को कच्छ, देवभूमि द्वारका, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, नवसारी, वलसाड, दमन और दादरा नगर हवेली में ऑरेंज अलर्ट दिया गया हैं

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने पिछले 7 वर्षों के दौरान 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' के तहत 84,119 बच्चों को बचाया

पिछले सात वर्षों में, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) 'नन्हे फरिश्ते' नामक एक ऑपरेशन में अग्रणी रहा है।

यह एक मिशन जो विभिन्न भारतीय रेलवे जोनों में पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए समर्पित है। पिछले सात वर्षों (2018-मई 2024) के दौरान, आरपीएफ ने स्टेशनों और ट्रेनों में खतरे में पड़े या खतरे में पड़ने से 84,119 बच्चों को बचाया है। 'नन्हे फरिश्ते' सिर्फ एक ऑपरेशन से कहीं अधिक है; यह उन हजारों बच्चों के लिए एक जीवन रेखा है जो खुद को अनिश्चित परिस्थितियों में पाते हैं। 2018 से 2024 तक का डेटा, अटूट समर्पण, अनुकूलनशीलता और संघर्ष क्षमता की कहानी दर्शाता है। प्रत्येक बचाव समाज के सबसे असुरक्षित सदस्यों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।

वर्ष 2018 में 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' की महत्वपूर्ण शुरुआत हुई। इस वर्ष, आरपीएफ ने कुल 17,112 पीड़ित बच्चों को बचाया, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। बचाए गए 17,112 बच्चों में से 13,187 बच्चों की पहचान भागे हुए बच्चों के रूप में की गई, 2105 लापता पाए गए, 1091 बच्चे बिछड़े हुए, 400 बच्चे निराश्रित, 87 अपहृत, 78 मानसिक रूप से विक्षिप्त और 131 बेघर बच्चे पाए गए। वर्ष 2018 में इस तरह की पहल की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हुए ऑपरेशन के लिए एक मजबूत नींव रखी गई।

वर्ष 2019 के दौरान, आरपीएफ के प्रयास लगातार सफल रहे और लड़कों और लड़कियों दोनों सहित कुल 15,932 बच्चों को बचाया गया। बचाए गए 15,932 बच्चों में से 12,708 भागे हुए, 1454 लापता, 1036 बिछड़े हुए, 350 निराश्रित, 56 अपहृत, 123 मानसिक रूप से विक्षिप्त और 171 बेघर बच्चों के रूप में पहचाने गए। वर्ष 2020 कोविड महामारी के कारण चुनौतीपूर्ण था, जिसने सामान्य जीवन को बाधित किया और परिचालन पर काफी प्रभाव डाला। इन चुनौतियों के बावजूद, आरपीएफ 5,011 बच्चों को बचाने में कामयाब रही।

वर्ष 2021 के दौरान, आरपीएफ ने अपने बचाव कार्यों में पुनरुत्थान देखा, जिससे 11,907 बच्चों को बचाया गया। इस वर्ष पाए गए और संरक्षित किए गए बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 9601 बच्चों की पहचान भागे हुए के रूप में, 961 लापता के रूप में, 648 बिछड़े हुए, 370 निराश्रित, 78 अपहृत, 82 मानसिक रूप से विकलांग और 123 बेघर बच्चों के रूप में पहचाने गए।

वर्ष 2023 के दौरान, आरपीएफ 11,794 बच्चों को बचाने में सफल रही। इनमें से 8916 बच्चे घर से भागे हुए थे, 986 लापता थे, 1055 बिछड़े हुए थे, 236 निराश्रित थे, 156 अपहृत थे, 112 मानसिक रूप से विकलांग थे, और 237 बेघर बच्चे थे। आरपीएफ ने इन असुरक्षित बच्चों की सुरक्षा और उनकी अच्छी देखभाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2024 के पहले पांच महीनों में, आरपीएफ ने 4,607 बच्चों को बचाया है। जिसमे 3430 घर से भागे हुए बच्चों को बचाया गया है, शुरुआती रुझान ऑपरेशन 'नन्हे फरिश्ते' के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण देते हैं। ये संख्या बच्चों के भागने की लगातार जारी समस्या तथा उन्हें अपने माता पिता के पास सुरक्षित पहुंचने के लिए आरपीएफ के किए गए प्रयासों दोनों को दर्शाती हैं।

आरपीएफ ने अपने प्रयासों से, न केवल बच्चों को बचाया है, बल्कि घर से भागे हुए और लापता बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई है, जिसमे आगे की कार्रवाई और विभिन्न हितधारकों से समर्थन मिला। आरपीएफ का ऑपरेशन का दयारा लगतार बढ़ रहा है, रोज नई चुनौतियों का सामना कर भारत के विशाल रेलवे नेटवर्क में बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर बच्चों की पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है। 135 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्पडेस्क उपलब्ध है।आरपीएफ मुक्त कराए गए बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति को सौंप देती है । जिला बाल कल्याण समिति बच्चों को उनके माता-पिता को सौंप देती है।

मिआ बाए तनिष्क के 'नेवर बिफोर सेल' में आकर्षक ऑफर्स का लाभ उठाइए

जुलाई, 2024: भारत के सबसे बड़े फाइन ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक, मिआ बाए तनिष्क ने 'नेवर बिफोर सेल' की घोषणा की है। इस एक्सक्लूसिव ऑफर में उपभोक्ताओं को मेकिंग चार्जेस पर मिलेगी 110ङ* तक की छूट, स्टाइलिश आभूषणों को बहुत ही आकर्षक कीमतों में खरीदने का यह सुनहरा मौका है। एक से बढ़कर एक, बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश आभूषणों की विशाल श्रेणी को इस सेल में शामिल किया गया है, आभूषणों से प्यार करने वाले हर व्यक्ति को इसमें अभूतपूर्व ख़ुशी मिलेगी।

मिआ बाए तनिष्क के इस अपनी तरह के अनोखे ऑफर में 1 आभूषण की खरीदी पर मेकिंग चार्जेस पर 50ङ की छूट मिलेगी, 2 आभूषण खरीदने पर मेकिंग चार्जेस पर 100ङ छूट मिलेगी। 4 आभूषण खरीदने पर उनमें से सबसे कम कीमत का आभूषण फ्री मिलेगा। आपके पुराने तनिष्क या मिआ प्रोडक्ट एक्सचेंज कीजिए और ऊपर दी गयी ऑफर्स के अलावा पाइए 10ङ अतिरिक्त छूट। 18 जुलाई से शुरू हो रहे इस सेल में मिआ बाए तनिष्क की अपने उपभोक्ताओं को मूल्य प्रदान करने की प्रतिबद्धता रेखांकित की जाएगी। सेल का सबसे ज़्यादा लाभ उठाने के लिए स्टोर में आकर खरीदारी करें, यादगार खरीदारी की ख़ुशी और संतुष्टि पाएं।

शेमारूमी पर गुजराती क्राइम कॉमेडी फिल्म 'कमठाण' का वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर

अहमदाबाद : क्राइम और कॉमेडी यह दोनों शैलियां एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं, जो दर्शकों को मनोरंजन का एक अलग अनुभव देते हैं। ऐसे में जब ये दोनों शानदार दुनिया एकदूसरे से मिल जाएं, तो मनोरंजन के एक नए आयाम का सृजन करती हैं। शेमारूमी जल्द ही अपने दर्शकों को यह अनुभव कराने उनकी स्क्रीन पर गुजराती क्राइम कॉमेडी फिल्म 'कमठाण' के वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर को प्रस्तुत करने जा रहा है। इस फिल्म में हितु कनोडिया, दर्शन जरीवाला, संजय गोराडिया, अरविंद वैद्य, दीप वैद्य और क्रुणाल पंडित जैसे अनुभवी कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

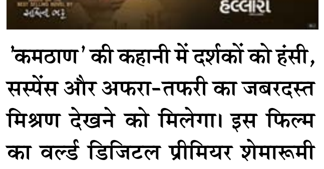

'कमठाण' की कहानी में दर्शकों को हंसी, सस्पेंस और अफरा-तफरी का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा। इस फिल्म का वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर शेमारूमी पर इस 18 जुलाई, 2024 को होगा।

'कमठाण' अश्विनी भट्ट के बेस्ट-सेलिंग उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में एक चोर और पुलिस वाले के बीच की मजेदार खींचातानी दिखाई गई है। यह कहानी एक चोर के इर्द-गिर्द घूमती है जो हाल ही में प्रमोट हुए पुलिस अधिकारी के घर को लूट लेता है, जिसके बाद एक नई दौड़ शुरू होती है, जो यात्रा हंसी और अफरा-तफरी से भरी होती है। ऐसे में क्या चोर पुलिस को मात देगा, या कानून उसे आखिरकार पकड़ लेगा? यह दिलचस्प कहानी और इसके हास्यपूर्ण मोड़ दर्शकों को एक अविस्मरणीय मनोरंजन अनुभव देने का वादा करते हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म 'हेलारो' के निर्माता अभिषेक शाह द्वारा निर्मित 'कमठाण' को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए नामांकित किया गया था।

साणंद स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनें निरस्त रहेगी

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल पर अहमदाबाद-विरमगाम सेक्शन में अइण्णध्थ के साणंद (दक्षिण) स्टेशन से साणंद स्टेशन की कनेक्टिविटी के संबंध में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते अहमदाबाद मण्डल से चलने/गुजरने वाली कुछ ट्रेनें निरस्त रहेगी। इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

निरस्त ट्रेनें:- 1) 20 जुलाई, 2024 की ट्रेन संख्या 09460 विरमगाम-अहमदाबाद मेमू निरस्त रहेगी। 2) 20 और 21 जुलाई, 2024 की ट्रेन संख्या 19119 गांधीनगर कैपिटल-वेरावल एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। 3) 19 और 20 जुलाई, 2024 की ट्रेन संख्या 19120 वेरावल-गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। 4) 20 जुलाई, 2024 की ट्रेन संख्या 09456 भुज-गांधीनगर कैपिटल स्पेशल निरस्त रहेगी। 5) 20 जुलाई, 2024 की ट्रेन संख्या 09455 गांधीनगर कैपिटल-भुज स्पेशल निरस्त रहेगी। 6) 19 और 20 जुलाई, 2024 की ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा-जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। 7) 20 और 21 जुलाई, 2024 की ट्रेन संख्या 22960 जामनगर-वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

ट्रेनों के परिचालन, समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री **www.enquiry.indian rail.gov.in** पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे

विभिन्न कार्य

मंडल रेल प्रबंधक (डब्ल्यूए) पश्चिम रेलवे, छठी मंजिल, इंजीनियरिंग। विभाग मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400008, ई-निविदा संख्या 1: बीसीटी/24-25/109 दिनांक 15.07.2024 को आमंत्रित करता है। कार्य और स्थानः अमलनेर (गुड्स शेड):- गुड्स शेड पीएफ कवर शेड का विस्तार 400 मीटर × 12 मीटर और मजदूरों के लिए 2 पानी के फव्वारे की आवश्यकता। लगभग कार्य की लागतः रु.3,52,18,078.24. ईएमडीः रु. 3,26,100/-. ई-निविदा संख्या 2: बीसीटी/24- 25/110 दिनांक 15.07.2024। कार्य और स्थानः उकाई सोंगहाड-जलगांव खंडः - सिंदखेड़ा - 02 वर्ष की अवधि के लिए स्टेशन, पी.एफ और स्टाफ क्वार्टरों के लिए 40000 लीटर/दिन की दर से पीने योग्य पानी की आपूर्ति। लगभग कार्य की लागतः रु.15,24,532. ईएमडीः रु. 30,500/-। दोनों निविदाएं जमा करने की तिथि और समयः 09.08.2024, 15:00 बजे तक। दोनों निविदाएं खोलने की तिथि और समयः 09.08.2024 को 15:00 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ireps.gov.in पर जाएं। नियमावली प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा. 0350

हमें लाइक करे facebook.com/westernRly

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादकः लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन

E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोनः 079-22921482 Mob.9375504122 , 93270864 7

R.N.I. 63177/ 95